राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 241 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, गुरुवार, 25 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

अदालत ने दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया मांगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक अदालत ने 'टूलकिट' मामले में अधिकार कार्यकर्ता शांतनु मुलुक की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया मांगी है। एएसजे धमेंद्र राणा संबंधित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान ने अदालत ने यह भी नोटिस किया कि बम्बई उच्च न्यायालय से शांतनु को 16 से 26 फरवरी तक के लिए ट्रांजिट जमानत मिली थी। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने 'टूलकिट' मामले में बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका को यह कहते हुए मंजूरी दे दी थी कि उनके (सुश्री रवि) के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

अनंतनाग में मुठभेड़ दो आतंकवादी ढेर

श्रीनगर, (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने जिले के श्रीगुफवारा क्षेत्र के शालगुल जंगलों में तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान उस वक्त मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने कहा कि अब तक मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर किया गया है।

मथुरा में सड़क हादसे में सात लोगों की मौत

मथुरा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में मथुरा के नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर टैंकर की चपेट में आने से कार सवार एक परिवार के छह सदस्यों समेत सात लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे माइलस्टोन 68 के पास यह हादसा उस समय हुआ जब वृंदावन से दर्शन कर हरियाणा के जींद जिले स्थित अपने घर लौट रहे एक परिवार की कार डिवाइडर तोड़ कर दूसरी लेन में आये टैंकर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर मौत हो गयी। डीजल से भरा टैंकर नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा था।

अल्मोड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट निलंबित

नैनीताल, (एजेंसी)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा शुरू होने का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है । श्रीवास्तव पर आरोप थे कि वह और उनके परिवार के सदस्य घूमने तथा दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए चंद्रमोहन सेठी नाम के व्यक्ति के निजी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की जांच कराई गई जिनमें श्रीवास्तव दोषी पाए गए। वहीं सेठी का एक केस की सुनवाई श्रीवास्तव की अदालत में होनी थी।

दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला आज से शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन करेंगे। मेला 27 फरवरी तक चलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए मेले की व्यवस्था की गई है। मेले का सजीव प्रसारण किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक किसान इसे देख सकें। मेले में रबी फसलों, सब्जियों और फूलों का प्रदर्शन किया जायेगा । इसके साथ ही उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बीजों की बिक्री भी की जाएगी।

तेलंगाना में दुर्घटनास्थल से चुराया दो किलो सोना

हैदराबाद, (एजेंसी)। तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को 108 एंबुलेंस के ड्राइवर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को एक हादसाग्रस्त कार से करीब ढाई किलो सोने के जेवर चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कार हादसे में कार में बैठे दो लोगों की मौत हो गई थी। पेद्दापल्ली जिले की पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए सोने के दो व्यापारियों के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों का पता लगा लिया था। दरअसल, दुर्घटना में मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दो एंबुलेंस मौके पर पहुंची थीं। उन्होंने 3.300 किलो सोने के गहने सौंपते हुए कहा कि उन्हें यह मृतकों के पास से मिले थे।

एक मार्च से होगा शुरू कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण

60 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगा टीका, फ्री सिर्फ सरकारी अस्पतालों में

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोरोना वायरस रोधी टीका सरकारी केंद्रों पर निशुल्क लगाया जाएगा। वहीं, निजी क्लीनिकों एवं केंद्रों पर उन्हें इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय का निर्णय किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि एक मार्च से होने वाला टीकाकरण दस हजार सरकारी और 20 हजार प्राइवेट सेंटरों पर हो सकेगा। सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, जबकि प्राइवेट में पैसे देने पड़ेंगे। जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो लोग प्राइवेट अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहेंगे, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अस्पतालों और मैन्युफैक्चरर्स से बात करने के बाद आने वाले दो-तीन दिनों में प्राइवेट सेंटर पर लगने वाले पैसों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय फैसला ले लेगा। इस बीच, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके अधिकांश सहयोगी अपने टीकों का भुगतान करेंगे।

केंद्र ने राज्यों में भेजे उच्चस्तरीय दल

केन्द्र ने महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्थिति से निपटने में मदद के लिए अपने उच्च स्तरीय दल भेजे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तीन सदस्यीय बहु-विशेषज्ञता वाले दलों का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये दल राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में हाल ही में बढ़े कोविड के मामलों के कारण का पता लगाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। ये कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कदम उठाने के वास्ते राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

देश में 24 घंटे में 104 मरे

देश में 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 104 पर पहुंच गयी जबकि इससे पहले तीन दिन तक यह आंकड़ा 100 से कम था हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई। इस बीच देश में अब तक एक करोड़ 21 लाख 65 हजार 598 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में गत 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13,742 नये मामले सामने आये और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ 10 लाख 30 हजार से अधिक हो गया है।

लातूर में एक छात्रावास के पांच कर्मचारी और 40 छात्र निकले संक्रमित

औरंगाबाद, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर शहर में एक छात्रावास के पांच कर्मचारी और 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। लातूर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण देशमुख ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि छात्रावास में रहने वाले 300 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों का कोरोना परीक्षण कराया गया जिनकी रिपोर्ट मंगलवार को आयी जिसमें 40 छात्र और पांच कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाये गये। सभी संक्रमित छात्रों और कर्मचारियों को कोविड केंद्र में क्वारंटीन कर दिया गया है।

देश में 24 घंटे में 13,742 नए मामले

भारत में एक दिन में कोविड-19 के 13,742 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,30,176 हो गई। इनमें से 1,07,26,702 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वायरस से पिछले 24 घंटे में 104 और लोगों की मौत हुई, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 1,56,567 हो गई। आंकड़ों के अनुसार, कुल 1,07,26,702 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97.25 प्रतिशत हो गई। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है।

किसान इस पेशकश पर करें विचार तब करेंगे वार्ता

कृषि मंत्री तोमर ने सुझाया वार्ता का फॉर्मूला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के मसले पर बड़ी बात की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बुधवार को कहा कि यदि आंदोलन कर रहे किसान नेता नए कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक स्थगित रखने और इस दौरान संयुक्त समिति के माध्यम से मतभेद सुलझाने की केंद्र सरकार की पेशकश पर विचार करने को तैयार हों तो सरकार उनके साथ बातचीत को तैयार है।

एक कार्यक्रम से केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों और उनके कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की कोशिशें कर रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत की धमकी के सिलसिले में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। जब भी उनकी ओर से कोई पेशकश आएगी तो भारत सरकार हमेशा बातचीत करने को तैयार है।

राकेश टिकैत बोले, कृषि कानून वापस नहीं लिये तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ करेंगे संसद मार्च

जयपुर,(एजेंसी)। भारतीय कियान यूनियत (बीकेयू) नेता राकेश टिकैत मंगलवार को राजस्थान के सीकर में एक किसान रैली में कहा कि हमारा अगला आह्वान संसद के लिए मार्च के लिए होगा। अगर कृषि कानून वायस नहीं लिए जाएंगे तो इस बार चार लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। चुरू में राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात को आजाद करवाना है। गुजरात भी बंधन में है। वहां के लोग बाहर निकलना चाहते हैं तो उन पर मुकदमें होंगे और जेलों में बंद होंगे। आंदोलन जारी रहेगा। आपकी एक नजर खेत पर रहनी चाहिए दूसरी नजर दिल्ली में आंदोलन पर और तीसरी नजर संयुक्त किसान मोर्चे पर। संसदीय समिति बनाएं और वहां कुछ फसलों की खेती करवाएं।

गुजरात के मोटेरा में है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, भारत के लिए गर्व का विषय

अहमदाबाद, (एजेंसी)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के मोटेरा स्टेडियम पर गर्व जाहिर करते हुए कहा कि इस भव्य स्टेडियम की परिकल्पना व निर्माण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तभी पूरी कर ली गई थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम (विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम) का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह , गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और जय शाह भी मौजूद रहे।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2018 के नवंबर में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तब मुझे पता चला कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। आज भारत के लिए गर्व का पल है जब मोटेरा का 1 लाख 32 हजार सीटर स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव अहमदाबाद शहर को स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्टर की दृष्टि से पूरे विश्व में एक नई पहचान दिलाएगा। यह स्टेडियम विश्व में सभी सुविधाओं की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ है।

किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया

किसान सम्मान निधि योजना के दो साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री बोले

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो साल पूरे होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वे 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अभिन्न अंग बन रहे हैं।

मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज दो साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई-बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के जीवन को आसान बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का जो संकल्प देश ने लिया है, उसमें पीएम किसान निधि की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी अभिन्न अंग बन रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपए जमा करती है। सरकार यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का पेट भरने वाले मेहनतकश किसानों के जीवन में सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों का तप और जुनून प्रेरित करने वाला है। मोदी ने कहा कि पिछले सात सालों में केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें सिंचाई के लिए बेहतर प्रावधान से प्रौद्योगिक का इस्तेमाल, अधिक ऋृण और बाजार उपलब्ध कराने से लेकर उचित फसल बीमा और मिट्टी की सेहत संबंधी जांच पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ऐतिहासिक वृद्धि करने का सम्मान मिला।

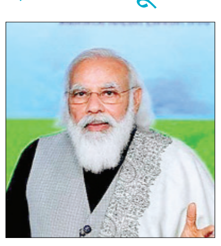

लव जिहाद विधेयक यूपी विधानसभा में पारित

अब विधान परिषद में होगी परीक्षा

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश विधान मंडल बजट सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को विधान सभा में पास करा लिया है। बुधवार को यूपी विधान सभा में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। हांलाकि अभी यह विधेयक विधान परिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा।

पिछले वर्ष नवंबर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया है। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसे कैबिनेट ने 24 नवंबर को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। नियम के अनुसार अध्यादेश को छह माह के भीतर विधान मंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होती है। इसी के तहत सरकार ने बुधवार को विधान सभा में विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया। अब सरकार इस विधेयक को विधान परिषद में ले जाएगी। यूपी में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है।

अध्यादेश के प्रमुख बिंदु

अध्यादेश के तहत जबरन धर्मांतरण के मामलों में एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अब जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अपराध होगा। विवाह के जरिये एक से दूसरे धर्म में परिवर्तन भी कठोर अपराध की श्रेणी में होगा। यह अपराध गैरजमानती होगा।

- सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल संबंधित सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- अध्यादेश के उल्लंघन की दोषी किसी संस्था या संगठन के विरुद्ध भी सजा का प्रावधान होगा।
- जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में साक्ष्य देने का भार भी आरोपित पर होगा। यानी कपटपूर्वक, जबरदस्ती या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन किए जाने के मामलों में आरोपित को ही साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ।
- यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती होगा। अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा।
- यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एक मात्र प्रयोजन विवाह के लिए किया गया तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा।
- पीड़िता या पीड़ित के अलावा उसके माता-पिता, भाई-बहन या रक्त संबंधी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे।

पहल | पेट्रोलियम मंत्री का जीएसटी काउंसिल से लगातार अनुरोध

तेल उत्पाद को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा

नई दिल्ली ■ एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि तेल उत्पाद को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा, तभी ग्राहकों को सीधा लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि हम इसके लिए जीएसटी काउंसिल से लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला काउंसिल को ही करना है कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएं या नहीं।

ध्यान रहे कि देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें नया रिकॉर्ड बना रही हैं। बावजूद इसके कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हैं। प्रधान का कहना है कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। तेल उत्पादक देशों ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है। अधिक लाभ के लिए तेल उत्पादक देश ऐसा कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ओपेक और ओपेक प्लस देशों से आग्रह कर रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि बदलाव जल्द होगा। प्रधान ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने का दूसरा कारण विकास कार्य हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कर एकत्र करते हैं। विकास कार्यों पर खर्च करने से ही अधिक रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने अपने निवेश में वृद्धि की है और इस बजट में 34 फीसदी अधिक पूंजी व्यय किया जाएगा।

पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को केंद्र सरकार पहले कई बार खारिज कर चुकी है। तब सरकार का तर्क था कि इससे लोगों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार के मुताबिक, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में लाने से राज्यों की कमाई पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। अगर तेल उत्पाद जीएसटी में आते हैं तो भी उन पर 28 फीसदी टैक्स के बाद सेस लगाया जाएगा। इसका लाभ ग्राहकों के बजाए तेल कंपनियों को मिलेगा। ग्राहकों के लिए कीमतों में किसी भी तरह का अंतर देखने को नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत इस समय 91 रुपए है तो डीजल 81 रुपए के आंकड़े के पास पहुंच गया है। तेल के दामों में दो दिनों तक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद फिर से दाम बढ़ गए। विपक्ष तेल के दामों पर लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है।

लगातार बढ़ती कीमतों से लोग हलकान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने लोगों को हलकान किया हुआ है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये के ऊपर पहुंच गई है। बीते दिनों सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि की। प्रतिदिन बढ़ रही तेल की कीमत नए-नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। देश में ग्राहक पेट्रोल व डीजल के बेस प्राइस यानी एक्स फैक्टरी का लगभग तीन गुना ज्यादा दे रहे हैं। बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से आम आदमी भी परेशान है।

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राज्यमंत्री श्री सोम प्रकाश, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री अशोक बेदी (अतिरिक्त सचिव पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष श्री विजय सांपला को बधाई देते हुए।

न्यूजीलैंड में बिना तारों के होगी बिजली सप्लाई: माइक्रोवेव बीम के रूप में घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी, इंसान-अन्य डिवाइस को खतरा नहीं

ऑकलैंड। बिना तारों के बिजली की सप्लाई की कल्पना साकार होने वाली है। आने वाले महीनों में न्यूजीलैंड की एक फर्म एमरोड, ऊर्जा वितरण कंपनी पावरको और टेस्ला मिलकर इसका ट्रायल करने जा रहे हैं। ये तीनों ऑकलैंड उत्तरी द्वीप में स्थित एक सोलर फार्म से कई किमी दूरदराज स्थित बस्तियों में बीम एनर्जी के जरिए बिजली पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के तहत माइक्रोवेव की बहुत पतली बीम के रूप में बिजली पहुंचाई जाएगी। पावर बीमिंग की इस प्रक्रिया का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन यह सेना से जुड़े काम और अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोगों तक ही सीमित था। 1975 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने माइक्रोवेव के जरिए 1.6 किमी दूरी तक 34.6 किलोवॉट बिजली भेजने का रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं किया गया।

एमरोड कंपनी के फाउंडर ग्रेग कुशनिर ने बताया कि हम शुरुआत में 1.8 किमी तक कुछ किलोवॉट बिजली भेजेंगे। धीरे-धीरे दूरी और पावर में बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे दूरदराज इलाकों में बिजली भेजने पर तारों के भारी भरकम खर्च से निजात मिलेगी। कुशनिर के मुताबिक बिना तारों के बिजली पहुंचाने की दो और टेक्नोलॉजी पर उनकी कंपनी काम कर रही है। इनमें से एक रिले है, ये निष्क्रिय उपकरण है। यह लैंस की तरह काम करता है और माइक्रोबीम को रीफोकस करके कम से कम ट्रांसमिशन लॉस के जरिए बिजली पहुंचाता है। दूसरे मेटामटेरियल्स हैं। ये पहले से ही क्लोकिंग डिवाइस में लगाए जाते रहे हैं। ये युद्धपोत और लड़ाकू विमान को रडार से बचने में मदद करते हैं। पर साथ ही ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को बिजली में बेहतर तरीके से बदलने में सक्षम हैं। एमरोड के अलावा सिंगापुर की ट्रांसफरफाई, अमेरिका की पावरलाइट टेक्नोलॉजी भी हवा से बिजली भेजने की योजना पर काम कर रही हैं।

म्यांमार में तख्तापलट: फेसबुक ने सरकारी टीवी चैनल के पेज ब्लॉक किए, मिलिट्री शासन के खिलाफ अब लोगों ने शुरू किया मिशन 22222

म्यांमार। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद सेना और यहां के नागरिक आमने-सामने हैं। इस बीच फेसबुक ने म्यांमार के सरकारी टेलीविजन एमआरटीवी और एमआरटीवी लाइव पेज को फेसबुक से हटा दिया है। एक दिन पहले ही चैनल ने मिलिट्री शासन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को चेताया था। इस बीच यंगून में मिलिट्री शासन के खिलाफ अब लोगों ने मिशन 22222 शुरू किया है।म्यांमार के यंगून शहर में सोमवार को लोगों ने मिशन 22222 शुरू किया है। दरअसल, सोमवार को 22-02-2021 है। यानी कैंपेन की तारीख में पांच बार दो है। इसलिए इसे ज्ञ2श ख्द्ध1द्ग नाम दिया गया। इस दिन से लोगों ने पूरे देश को शट डाउन करने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत लोग अब दुकान, ऑफिस बंद रखेंगे। कामकाजी लोग अपना काम बंद कर के मिलिट्री शासन का विरोध करेंगे। यह तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र बहाल नहीं हो जाता।

सेना की चेतावनी का असर नहीं

म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ हो रहे अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में देशभर में लाखों लोग शामिल हुए। सेना ने चेतावनी जारी कर कहा था कि प्रदर्शनकारी बाहर निकल कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा।

कई सड़कों के बंद होने के बावजूद हजार से अधिक प्रदर्शनकारी यंगून में अमेरिकी दूतावास के पास एकत्रित हो गए, लेकिन सेना के नजदीक पहुंचने के बाद किसी भी तरह के टकराव से बचने के लिए वे वहां से चले गए।

पाकिस्तान में सोशल वर्कर्स पर हमला-उत्तरी वजीरिस्तान में बदमाशों ने चलती कार पर फायरिंग की, 4 महिला एनजीओ कार्यकर्ताओं की मौत

वजीरिस्तान। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में बदमाशों ने चलती कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में कार सवार 4 महिला एनजीओ वर्कर्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया और हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

चारों कार्यकर्ता महिला अधिकार के लिए काम करती थीं

हमले में मारी गई महिलाएं सबावून पाकिस्तानी चैरिटी नाम की संस्था चलाती थीं। यह संस्था महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के साथ ही कुटीर उद्योग के जरिए उन्हें रोजगार मुहैया करवाने का काम करती है। चारों महिलाएं संस्था के काम से ही बन्नू से मीर अली जा रही थी। मीर अली इलाके की पुलिस के मुताबिक, हमलावरों को महिलाओं के आने की पहले से जानकारी थी। हमलावर उन्हीं को मारने आए थे। माना जा रहा है कि वारदात के बाद वे पास के पहाड़ों में भाग गए। अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस का अनुमान है कि यह पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों की करतूत हो सकती है। यह अफगान तालिबान से एक अलग विद्रोही गुट है।

इमरान का श्रीलंका दौरा:भारत ने इमरान को अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी

2 साल पहले मोदी को पाक के आसमान से गुजरने की इजाजत नहीं मिली थी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज दो दिन के श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन को अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और सऊदी अरब दौरे पर गए थे, तब पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट को अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी।

इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक, वीवीआईपी फ्लाइट्स को एयरस्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देनी होती है। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया था। भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया है।

दौरे से पहले इमरान को झटका: इमरान खान मंगलवार को दो दिन के दौरे पर श्रीलंका

पहुंच रहे हैं। हालांकि, इस दौरे के पहले ही उन्हें गोटबाया राजपक्षे की सरकार ने बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका दिया। इमरान अब श्रीलंकाई संसद को संबोधित नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि राजपक्षे ने यह कदम भारत की नाराजगी से बचने के लिए उठाया है। एक हफ्ते पहले जब इमरान के श्रीलंका दौरे का शेड्यूल तय किया गया था, इसमें संसद में भाषण का कार्यक्रम था। बाद में राजपक्षे सरकार को लगा कि इमरान कश्मीर का जिक्र कर सकते हैं, लिहाजा स्पीच को शेड्यूल से ही हटा दिया गया। श्रीलंका के अखबार 'कोलंबो गैजेट' में पाकिस्तान के एक्सपर्ट डार जावेद का आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसमें डार ने लिखा- बहुत साफ बात यह है कि श्रीलंका भारत की नाराजगी का जोखिम नहीं ले सकता।

वह पहले ही चीन के कर्ज में उलझा है और भारत वैक्सीन समेत हर मोर्चे पर उसकी मदद कर रहा है। हाल ही में भारत ने पांच लाख वैक्सीन श्रीलंका भेजे थे। वैसे भी यहां मुस्लिमों को लेकर बौद्ध समुदाय में नाराजगी रही है। जावेद के मुताबिक- 2012 में इमरान ने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि वो एक पवित्र युद्ध लड़ रहा है और इस्लाम में यह जायज है। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने मुस्लिमों का मुद्दा उठाया। अक्टूबर 2020 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने कट्टरपंथियों और अपने देश में आतंकी हमलों पर सख्त रुख अपनाया तो इमरान ने मैक्रों के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए। श्रीलंका सरकार को आशंका थी कि इमरान उनकी संसद का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कर सकते हैं।

राजपक्षे की मजबूरी

डार जावेद आगे लिखते हैं- श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। दोनों भाई हैं और बौद्ध समुदाय से आते हैं। वे जानते हैं कि अगर इमरान ने संसद में भाषण के दौरान इस्लामिक मामले उठाए तो श्रीलंका में भी इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। हाल ही में इमरान ने श्रीलंका में मुस्लिमों के हालात पर शिकायती लहजा दिखाया था।

श्रीलंका के एक मुस्लिम नेता राशिद बाथिउद्दीन ने पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी थी। उनका आरोप था कि कोविड-19 से मारे जा रहे मुस्लिमों को दफनाने की बजाए जलाया जा रहा है। इमरान ने सार्वजनिक तौर पर यह मुद्दा उठाया था।

अपना घर नहीं देखते इमरान

जावेद आगे लिखते हैं- इमरान को दूसरे मुल्कों में मुस्लिमों की हालत खराब लगती है, लेकिन हाल ही में ह की एक रिपोर्ट में कहा गया था पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेहद परेशान हैं। इमरान इस पर कुछ नहीं बोलते। कश्मीर मुद्दे पर वे मुस्लिम देशों को ही एकजुट नहीं कर पाए। कोई देश इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है।

कांगो में आतंकी हमला: यूनाइटेड नेशंस के काफिले पर आतंकियों ने गोलियां बरसाईं, इटली के राजदूत समेत 2 की मौत

इटली। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इटली के राजदूत लुका अटानासियो की हत्या कर दी गई। वह यूनाइडेट नेशंस के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनकी कार पर हमला कर दिया। इसमें 43 साल के लुका घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इटली के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यह हमला ईस्टर्न रीजनल कैपिटल गोमा के पास हुआ। इसमें एक सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई।लुका अटानासियो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जुड़े थे। संगठन ने कहा कि हमले में उसके सबसे बड़े सहयोगी की मौत हो गई। कई लोग घायल भी हुए हैं। यह डेलिगेशन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के तहत फील्ड ट्रिप पर था। जिस रास्ते से काफिला गुजर रहा था, उसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। काफिले के साथ सिक्योरिटी टीम नहीं थी। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। माना जा रहा है कि हमला किडनैपिंग के इरादे से किया गया था। हमले वाली जगह गोमा से 2 घंटे की दूरी पर है। राजधानी से बाहर सड़क पर निकलना खतरे से भरा होता है, क्योंकि यहां विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इस इलाके में बड़ी संख्या में यूएन के शांति सैनिक तैनात हैं। गोमा से बाहर जाने के लिए यूएन के काफिले को सुरक्षा मंजूरी लेनी होती है। यह इलाका नॉर्थ किवू प्रांत में आता है और विद्रोही गुट एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस का गढ़ है।

मंगल से आई आवाज: नासाने पर्सीवरेंस रोवर से भेजी गई पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की, 10 सेकंड के टेप में हवा जैसी मामूली आवाज

वाशिंगटन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की। 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में बहुत मामूली आवाज है।

नासा के मुताबिक, यह उसके पर्सीवरेंस रोवर के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल और मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुई। नासा ने इसके साथ ही लाल ग्रह पर पर्सीवरेंस रोवर की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया है। इस रोवर ने गुरुवार को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी।

लैंडिग के बाद माइक्रोफोन ने काम नहीं किया था

मीडिया रिपोर्ट्स में नासा के हवाले से कहा गया है कि गुरुवार को जब पर्सीवरेंस ने मार्स पर लैंडिंग की थी उस दौरान इसके माइक्रोफोन ने काम करना अचानक बंद कर दिया था। यही वजह है कि लैंडिंग के दौरान का इसका ऑडियो सामने नहीं आ

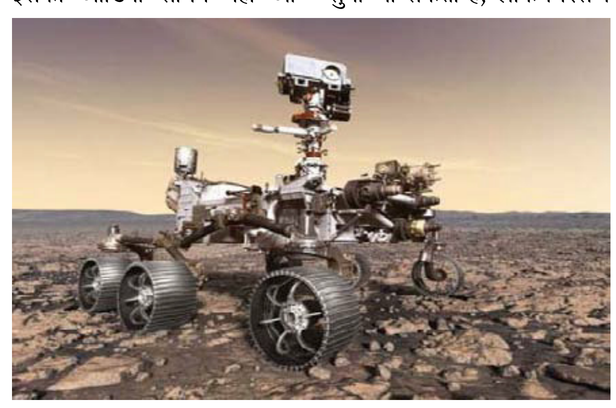

सका था। हालांकि, इसके बाद माइक्रोफोन ने काम करना शुरू कर दिया और अब इसकी पहली क्लिप नासा ने जारी की है। मिशन के कैमरा और माइक्रोफोन सेक्शन इंजीनियर डेव ग्रुएल ने कहा- 10 सेकंड के इस क्लिप में बहुत धीमी और मामूली आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन रिसर्च के लिहाज से यह बेहद कीमती है।

वीडियो क्लिप भी जारी

ऑडियो के साथ ही नासा ने एक लैंडिंग टाइम (टच डाउन) वीडियो जारी किया है। 3 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में तीन फ्रेम हैं। इसमें दिखता है कि रोवर ने कैसे लैंडिंग की। हीट शील्ड और पैराशूट भी नजर आते हैं। इसी वीडियो में नासा के स्टाफ की खुशी के पल भी कम्पाइल किए गए हैं। नासा ने कहा- यह इतिहास में पहली बार हुआ जब मार्स पर लैंडिंग का वीडियो और तस्वीरें ली गई हैं। हम इनका अध्ययन शुरू कर चुके हैं।

रोवर बिल्कुल सही हालत में: पर्सीवरेंस की मिशन मैनेजर जेसिका सैमुअल्स ने कहा- अब तक सभी चीजें वैसी ही हैं, जैसी हम चाहते थे। यह बिल्कुल हमारी उम्मीदों के मुताबिक ही काम कर रहा है। अब हम जल्द ही इसके साथ मौजूद हेलिकॉप्टर की पहली उड़ान पर फोकस करेंगे। फिलहाल, शुरुआती तैयारियां की जा रही हैं।

कोरोना दुनिया में: जो बाइडेन ने कोविड-19 से मारे गए 5 लाख अमेरिकियों को याद किया, कहा- मुझे इनके परिवारों के दर्द का अहसास है

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11.22 करोड़ से ज्यादा हो गया। 8 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 24 लाख 84 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

व्हाइट हाउस में श्रद्धांजलि

अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर 5 लाख पार कर गया। हालांकि, worldometers और दूसरी कोविड ट्रैकर वेबसाइट्स ने दो दिन पहले ही मरने वालों की संख्या पांच लाख बता दी थी। बहरहाल, राष्ट्रपति बाइडेन की मौजूदगी में इस महामारी से मारे गए अमेरिकियों को याद किया गया। व्हाइट हाउस में कैंडल जलाकर और मौन रखकर मारे गए अमेरिकियों को श्रद्धांजलि दी गई। बाइडेन ने कहा- हमें मजबूती से इसका सामना करना होगा। यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि एक चुनौती है। महामारी से मुकाबले के लिए सियासत और गलत जानकारी से बचना होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, 'जिन लोगों ने इस महामारी में अपने परिजनों को खोया है, मुझे उनके दर्द का गहरा अहसास है।' अमेरिकी इतिहास में किसी एक वजह या दौर से इतनी मौतें पहले कभी नहीं हुईं। सेकंड वर्ल्ड वॉर में करीब 4 लाख 5 हजार अमेरिकियों की मौत हुई थी। वियतनाम वॉर में 58 हजार और कोरिया के साथ जंग में 36 हजार लोगों की मौत हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने

आशंका जताई है कि 1 जून तक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख 89 हजार तक पहुंच सकता है।

'द गार्डियन' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इटली ने पिछले साल फरवरी में WHO को महामारी के बारे में सही जानकारी नहीं दी, जबकि देश में केस मिलने शुरू हो गए थे। दरअसल, दुनिया के तमाम देशों को इंटरनेशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स का पालन करना होता है। साल की शुरुआत में बीमारियों से जुड़ी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट देनी होती है। इटली ने 4 फरवरी 2020 को यह रिपोर्ट तो दी, लेकिन इसमें खुद को लेवल 5 पर बताया। इसके मायने ये हैं कि किसी बीमारी से लड़ने की उसकी तैयारी सही स्तर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, इटली ने 2006 के बाद राष्ट्रीय महामारी उन्मूलन यानी महामारी से निपटने का प्लान ही अपडेट नहीं किया। दावा किया जाता है कि अमेरिका से पहले इटली में महामारी ने दस्तक दी। चीन के बाद यह पहला देश था जहां महामारी सबसे पहले पैर पसार चुकी थी।

ब्रिटेन सरकार की तैयारी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में लॉकडाउन हटाने का रोडमैप जारी कर किया। 4 स्टेप में लॉकडाउन हटाया जाएगा। इनकी तारीखों का ऐलान करते वक्त जॉनसन ने कहा कि खतरा अभी बरकरार है। आने वाले महीनों में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीजों और मौतों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी वैक्सीन पूरी आबादी को 100त्र प्रोटेक्शन का भरोसा नहीं दे सकती। जॉनसन ने बताया कि रोडमैप की सभी स्टेप के बीच 5 हफ्ते का अंतर होगा। किसी भी जल्दबाजी का मतलब दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आना भी हो सकता है और मैं यह खतरा नहीं उठाऊंगा। उन्होंने सांसदों से कहा कि हर स्टेप में हमारे फैसले पर तारीखों के बजाय डेटा की अहम भूमिका होगी।

पढ़ाई ने बदल दी जिंदगी: ब्राजील में किताब पढ़ने के शौक ने 3 पीढ़ी की नौकरानी को बना दिया स्टार; अब लेखक, रैपर और टीवी होस्ट हैं

रोम। जॉइस फर्नांडीस अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नौकरानी थी। वह एक अपार्टमेंट में घर की देखभाल और साफ-सफाई का काम करती थी। जॉइस घंटों बुक-शेल्फ को साफ करती थी। इस बीच जॉइस को 'ओल्गा' रिवोल्यूशनरी एंड मार्टियर' नाम की किताब दिखी, जिसे उसने पढ़ना शुरू किया।जॉइस उस किताब को मालिक के बाहर जाने के बाद ही पढ़ती थी। उसे डर था कि यदि मालिक ने उसे किताब बढ़ते हुए देख लिया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक दिन उसके मालिक ने किताब पढ़ते देख लिया। उसने जॉइस को बुलाया और उसकी तारीफ की। फिर किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जॉइस ने किताबें पढ़ना शुरू किया। कॉलेज में दाखिला लिया और 2012 में उसने डिग्री हासिल की। इसके बाद जॉइस ने नौकरानियों के जीवन पर किताब लिखी, जो ब्राजील में चर्चा का विषय बनी। जॉइस ने टीवी पर कुछ प्रोग्राम होस्ट किए। यहां उन्होंने नौकरानियों और नस्लवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिर कला के जरिए अपनी आवाज बुलंद की और रैपर बन गई। वहीं अब जॉइस फर्नांडीस ब्राजील की स्टार बन चुकी हैं। लोग उन्हें प्रेटा रारा यानी अद्वितीय अश्वेत महिला के नाम से जाना जाता है।

न्यूज शेयरिंग पर समझौता: ऑस्ट्रेलिया में फिर न्यूज कंटेंट देगा फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार के बीच डील फाइनल

सिडनी। फेसबुक और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को खत्म हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का पालन करने को तैयार हो गया है। इस कानून को लेकर ही सरकार से उसका विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ था। इसके बाद फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पेज बंद कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने फेसबुक के सामने से झुकने से इंकार कर दिया था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस संबंध में मदद मांगी थी।

पेज री-स्टोर किए जाएंगे

ऑस्ट्रेलियाई सरकार से डील फाइनल होने के बाद फेसबुक ने एक बयान में कहा- आने वाले दिनों में हम न्यूज कंटेंट वाले पेज री-स्टोर कर देंगे। बैन खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा- फेसबुक से समझौता हो गया है। नए कानून के जरूरी मुद्दों पर वे हमारी शर्तें मानने तैयार हो गए हैं। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विल एस्टन ने कहा- हमने कुछ बदलाव किए हैं। अब कंपनी ऑस्ट्रेलिया में लोगों और पत्रकारिता के हित में इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी। इस डील के मायने ये हैं कि अब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स इस्तेमाल करने के

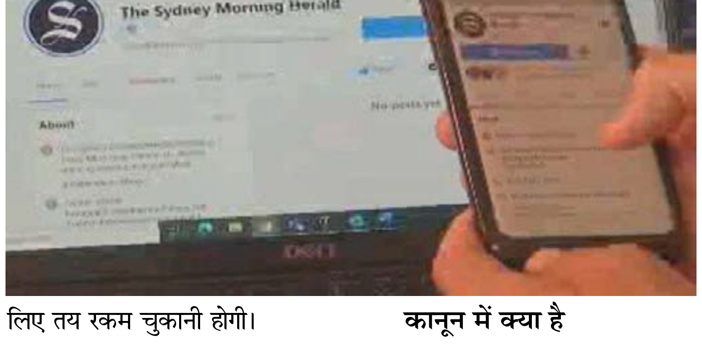

लिए तय रकम चुकानी होगी।

कानून में क्या है

कोरोना जब चरम पर था, उस दौरान फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन मीडिया हाउसेस को घाटा हुआ। उनको छंटनी करनी पड़ी। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज लिंक शेयर करके पैसा कमाते रहे। अब ऑस्ट्रेयाई सरकार ने जो कानून बनाया है, उसके मुताबिक-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर न्यूज कंटेंट शेयर करेंगे तो संबंधित कंपनी से प्रॉफिट शेयर करना होगा। फेसबुक और गूगल इसे मानने तैयार नहीं हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में सर्विसेस बंद करने की धमकी दे रहे हैं।

> फेसबुक और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच न्यूज कंटेंट शेयरिंग को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को खत्म हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का पालन करने को तैयार हो गया है। इस कानून को लेकर ही सरकार से उसका विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ था।

दबाव काम आया

फेसबुक चीफ मार्क जकरबर्ग ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई अफसरों से प्रस्तावित कानून के बारे में बातचीत की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने साफ कहा था- फेसबुक की धमकियों के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने देश और यहां की कंपनियों के हित जरूर देखेंगे। मॉरिसन ने टेक कंपनियों की धमकियों के आगे झुकने से इंकार कर दिया था और दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से इस बारे में बातचीत की थी। मॉरिसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फेसबुक की मनमानी पर लगाम लगाने में मदद मांगी थी।

द्वारका में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी से होगी पौधों की सिंचाई

पश्चिमी दिल्ली। राजधानी में भूमिगत जल स्तर काफी नीचे जाने से स्थिति दिनोदिन विकट रूप धारण कर रही है। ऐसे में पार्कों में पानी की दिक्कत नहीं हो इस दिशा में कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लिहाजा, अब दूसरी संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एक महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर उभरा है। पहले केशोपुर में इस प्लांट को लगाया गया, वहीं अब द्वारका सेक्टर 11 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर शुभारंभ कर दिया गया है। इस प्लांट के निर्माण पर 30 लाख रुपये की लागत आई है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नजदीक तीन पार्कों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि प्लांट में शोधित पानी का इस्तेमाल सिंचाई में की जा सके। इसे अगले 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस पर करीब दस लाख रुपये की लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने के बाद प्लांट से सीधे पानी पार्कों में पहुंच पाएगा। द्वारका बी की निगम पार्षद कमलजीत सहरावत ने कहा 'प्लांट के बगल से ही एक ड्रेन गुजर रहा है। इसी ड्रेन के पानी को साफ किया जाएगा। पौधों की सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। हमें पानी बचाने की दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। द्वारका सेक्टर 11 में शहीद हेमू पार्क में चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसपर 18 लाख रुपये की लागत आएगी। इसमें तीन मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। साथ ही एक मीटर स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी। इससे पार्कों के रखरखाव में आसानी होगी और असामाजिक तत्व के लोग यहां नहीं आ सकेंगे।' द्वारका इलाके में दो और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें एक द्वारका सेक्टर 17 में निर्माणाधीन है, वहीं एक अन्य के लिए जगह की तलाश की जा रही है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा पार्कों में शोधित पानी से सिंचाई करना है। इससे हरियाली बरकरार रखने में निगम को मदद मिलेगी।

सिंघु बॉर्डर पर किसानों के मंच से मिल रही प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी

नई दिल्ली। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वह मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी को मारने की धमकी दे रहे हैं। उनको न तो पुलिस का डर है और न ही किसी कार्रवाई का। जिस मंच से यह धमकियां दी जा रही हैं वह मंच किसी और का नहीं, बल्कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) का है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकियां देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो शनिवार का है। इसमें कई निहंग सिख नेता सिंघु बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मंच पर पहुंचते हैं। पहले बाबा नारायण सिंह व बाबा राज सिंह जैसे निहंग सिख नेता प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हैं। कोई उपद्रवियों को पनाह देने की बात करता है तो कोई हिंसा की। इसके बाद एक अन्य निहंग सिख नेता ने कहा, %पंजाब से पंगा लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गलती कर दी है। जब दो सिखों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में ढेर कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया तो मोदी की क्या चीज हैं। जिसने भी पंजाब की ओर रुख किया है मुंह की खाई है।% निहंग ने ये भी कहा, %ये मत सोचना की बाबा जोश में कह गया, बाद में मुकर जाएगा। जो बोला है उस पर खरे उतरेंगे। जिस समय ये भड़काऊ भाषण दिया जा रहा था उस समय कई प्रदर्शनकारी धरना स्थल के पास खालिस्तान समर्थक रहे जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर ट्रैक्टर पर लगाकर पहुंचे थे। जैसे ही निहंग मंच से उतर कर वापस गए, ट्रैक्टर भी उनके पीछे हरियाणा की ओर लौट गए। मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले दिन से अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मोदी के खिलाफ ऐसी धमकियां सिंघु बार्डर पर कई बार दी जा चुकी हैं। अंतर इतना है कि पहले ये धमकियां भीड़ में शामिल प्रदर्शनकारी देते थे, अब मंच से निहंग सिख नेता दे रहे हैं। चिन्मय बिश्वाल (प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस) के मुताबिक, पुलिस को लगातार उकसाया जा रहा है, लेकिन हम संयम से काम ले रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ सबूत इकट्ठे किये जा रहे हैं। ऐसे भाषण देने वालों की हर गतिविधि पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर में तल्ख हुए गर्मी के तेवर, 33 डिग्री तक पहुंचा तापमान

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार इजाफे से गर्मी के तेवर तल्ख होने लगे हैं। आलम यह है इस वर्ष फरवरी का महीना पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे गर्म रह सकता है। उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री अधिक 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 36 से 100 फीसद दर्ज किया गया। वहीं, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स इलाके में तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यहां न्यूनतम तापमान भी सबसे अधिक 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीतमपुरा में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

वहीं, स्काईमेट वेदर के विज्ञानियों के मुताबिक दिल्ली में सामान्य तौर पर फरवरी का पहला सप्ताह 23 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ शुरू होकर 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, ऐसे में पूरे माह का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन, बीते तीन सप्ताह की बात करें तो इस बार औसत अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है।

2016 में फरवरी का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस था। 2017 में यह 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। 2017 में 21 फरवरी को सबसे अधिक 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं, इस वर्ष और पिछले वर्षों की तुलना करें, तो 2020 का फरवरी काफी ठंडा रहा था। उधर, मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) मंगलवार को 250 दर्ज किया गया। एनसीआर के शहरों की बात करें तो गाजियाबाद का एक्यूआइ 320, नोएडा का 214, फरीदाबाद का 296, ग्रेटर नोएडा का 253 व गुरुग्राम 241 रहा। बुधवार सुबह से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग नजर आया, जिससे लोगों ने आंखों में जलन की भी शिकायत की है।

दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा में इलेक्ट्रिक वाहन संजीवनी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा में इलेक्ट्रिक वाहन संजीवनी हैं। जहां एक ओर हवा में सर्वाधिक जहर पेट्रोल और डीजल वाहनों का धुआं ही घोलता है वहीं ई-वाहन पूर्णतया धुआं रहित होते हैं। इनसे कोई प्रदूषण नहीं होता। लिहाजा, अगर दिल्ली- एनसीआर में सभी श्रेणियों के वाहनों को धीरे-धीरे ई-वाहनों में तब्दील कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर वायु प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली- एनसीआर के प्रदूषण में एक बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले धुएं का है। तमाम शोधपरक अध्ययन भी यह प्रमाणित कर चुके हैं। इसी वजह से यहां के प्रदूषण में पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे मुख्य प्रदूषण तत्वों की मात्रा भी कहीं अधिक है। चूंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है, लिहाजा निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। कहने को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी व्यावसायिक वाहन सीएनजी पर चल रहे हैं लेकिन आज की तारीख में वायु प्रदूषण फैलाने में सर्वाधिक भूमिका दोपहिया वाहनों, टैंपो और माल ढोने वाले तिपहिया वाहनों की है। ये सभी वाहन पेट्रोल और डीजल पर चल रहे हैं। इनको चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों में शिद्दत करना समय की मांग है। 10 बड़ी कंपनियां इसी साल इन सभी वाहनों के ई-वर्जन भी ला रही हैं। नेटवर्क नहीं बिछता, इन्हें एडप्टर से भी चलाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इनकी चार्जिंग घर पर भी हो सकेगी। दिल्ली और हरियाणा ने अपनी ई-वाहन नीति अधिसूचित भी कर दी है। यहां ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। दिल्ली सरकार ने तो ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान भी चलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक अपनी ई-वाहन नीति अधिसूचित नहीं की है, लेकिन वहां भी इस पर काम चल रहा है। ई-वाहन नीति को लेकर कोई हीलाहवाली न हो और मौजूदा वाहनों को ई-वाहनों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी रफ्तार पकड़े इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लगभग दो सप्ताह पूर्व दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिवों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चल रहे तमाम मौजूदा वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों में शिफ्ट करने का आदेश भी दिया है। और सरकारी इस्तेमाल के लिए अब जो भी वाहन खरीदे जाएं, वे इलेक्ट्रिक ही हों। प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वाहन चालकों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें ई-वाहन के फायदे बताए जाएं। उन्हें यह सुविधा भी दी जाए कि वे जहां जरूरत हो वाहन को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है।

अधिकारी संदिग्ध अवस्था में अपने घर में मिले घायल, अस्पताल में मौत

दक्षिणी दिल्ली। डिफेंस कालोनी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक आइएफएस अधिकारी संदिग्ध अवस्था में अपने घर में घायल मिले। उन्हें आनन-फानन में मूलचंद अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्व आइएफएस रंजीत सेठी अपने कमरे में गोली लगने से घायल अवस्था में मिले थे। दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 7¬45 मिनट पर डिफेंस कालोनी पुलिस को एक व्यक्ति के गोली लगने और एंबुलेंस की जरूरत को लेकर सूचना मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को जानकारी मिली कि 81 वर्षीय रंजीत सेठी अपने कमरे में गोली लगने से घायल हुए थे। उन्हें तुरंत मूल चंद अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

लाडले ताज के सिर पर कौन रखेगा हाथ शबनम की फांसी को लेकर निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह नाराज

नई दिल्ली। अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता समेत परिवार के साथ 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाली शबनम को फांसी देने की तैयारी चल रही है। शबनम की फांसी को लेकर डेथ वारंट भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में 2012 के निर्भया केस की तरह यह फांसी भी चर्चा में आ चुकी है।

शबनम की फांसी को लेकर निर्भया के चारों दोषियों के वकील एपी सिंह का अहम बयान आया है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है- शबनम और सलीम प्रकरण में फांसी देने की बात चल रही है। आजादी के बाद देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। यह दुखद है। फांसी किसी समस्या का इलाज नहीं है। पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं। दोषी की मनोदशा का खत्म करना चाहते थे तो उसमें सुधार लाइये। जेल को सुधार गृह रखिये... फांसीघर मत बनाइये। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो 100 से अधिक देशों में फांसी की सजा खत्म हो चुकी है। बता दें कि निर्भया के चारों दोषियों पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को पिछले साल 20 मार्च की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील एपी सिंह ने शबनम की फांसी देने की मांग पर कहा कि फांसी किसी समस्या का इलाज हो ही नहीं सकता है। इंसानी समाज और सभ्य समाज में आंख के बदले आंख लेंगे तो तो एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। कांटों के बदले कांटों की बात करेंगे तो एक दिन सड़कों पर कांटे होंगे और लोगों को पांव में छाले।

लगातार फांसी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले वकील एपी सिंह ने शबनम की फांसी को लेकर कहा कि यह बेहद दुखद है। आजाद भारत में पहली महिला को फांसी दी जाने वाली है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जेल को सुधार गृह रह देना चाहिए फांसीघर नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि जेल में जन्में सलीम और शबनम के बेटे मुहम्मद ताज ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई है।

बेटे ताज ने दया याचिका में लिखा है- राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो। इस पर निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि इसमें शबनम के बच्चे ताज का क्या कसूर है। उसका तो एक ही सहारा उसकी मां है। एपी सिंह का कहना है कि जब सलीम और शबनम को फांसी हो जाएगी तो वह बच्चा तो अनाथ हो जाएगा। एपी सिंह का कहना है कि मां शबनम को फांसी लगने वाली है। अगला नंबर पिता सलीम का है, जाहिर है उसे भी आने वाले महीनों में फांसी दे दी जाएगी। जरा, सोचिये...इंसाफ किसे मिला। माता-पिता को फांसी लगते ही वह बेचा ताज तो अनाथ हो जाएगा। ये कैसा इंसाफ है, जिसके होते ही एक बच्चा अनाथ हो रहा है। उस बच्चे ताज के सिर कौन मां आकर मुश्किल घड़ी में हाथ रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील एपी सिंह ने निर्भया के दोषियों को फांसी से बचाने की अंतिम समय तक कोशिश की थी। 20 मार्च को सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर चारों दोषियों को फांसी देने से पहले 19 मार्च की सुबह से लेकर रातभर तक दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कार्यवाही चली थी। यहां तक 20 मार्च की तड़के 2 बजकर 30 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर मुहर लगाई थी।

उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद शबनम की फांसी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन शबनम को फांसी दिए जाने के लिए मथुरा की जेल में सारी तैयारी तो कर ली गई है। माता-पिता समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या में दोषी शबनम को फांसी देने के लिए सरकारी वकील की ओर से मथुरा के जिला जज के पास डेथ वॉरंट जारी करने की मांग रखी गई थी। वहीं, राजभवन में शबनम की दया याचिका लंबित होने के कारण जज ने वॉरंट जारी करने से मना कर दिया।

उधर, जहां दरअसल, शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मां-बाप, भतीजे, 2 भाई, एक भाभी और रिश्ते की बहन को पहले दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया फिर रात को बेहोशी की हालत में एक-एक करके सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। इसी मामले में शबनम और सलीम को फांसी दी जानी है।

पढ़ी-लिखी शबनम एक 8वीं फेल सलीम से प्यार करती थी। जाहिर है कि माता-पिता के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो रिश्ते के लिए मना कर दिया गया। इसके बाद प्रेम में अंधी शबनम ने ऐसा खूनी खेल खेला कि इतिहास बन गया। 14 अप्रैल 2008 की रात को अमरोहा के हसनपुर तहसील के गांव बावनखेड़ी में खूनी खेल हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक, शबनम ने प्रेमी सलीम से साजिश के तहत कहा कि वह उसे नशे की गोलियां लाकर दे जिससे सभी को बेहोश कर उन्हें मारा जा सके. सलीम ने 10 गोलियां मेडिकल से लाकर शबनम को दे। सलीम ने ऐसा ही किया। फिर शबनम ने गोलियां दूध में मिलाकर पूरे घर को दे दीं, लेकिन 11 साल के भतीजे को दूध नहीं दिया। नशे वाला दूध पीकर जब सब बेहोश हो गए तो सलीम और शबनम ने कुल्हाड़ी से सबका गला काट दिया।नजदीक के ट्यूबवेल पर खून से सने हाथ-पैर धोने के बाद जब शबनम ने देखा कि उसका भतीजा जीवित रह गया है तो 11 साल के भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी। निचली अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी शबनम-सलीम की फांसी पर मुहर लगा चुका है।

रेल यात्रा के दौरान रहें सावधान, 29 लाख लोगों से रेलवे ने वसूले 141 करोड़

नई दिल्ली। बिना टिकट लिए सफर करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती है। इन्हें रोकने लिए बीच-बीच में विशेष अभियान चलाया जाता है। पकड़े जाने पर अच्छा खासा जुर्माना भी वसूला जाता है। उत्तर रेलवे में पिछले तीन सालों में बे टिकट यात्रियों से 141.71 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया है।

बावजूद इसके यह समस्या बरकरार है। कोरोना संकट के दौर में जबकि रेलवे स्टेशनों पर सख्ती है और बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर पहुंचना मुश्किल है, फिर भी लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दस माह में ही लगभग 74 हजार बिना टिकट यात्री पकड़े गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोरोना संकट से पहले उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के साथ ही फिरोजपुर, अंबाला, मुरादाबाद व लखनऊ मंडल के बड़े स्टेशनों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा था। कोरोना काल में लगभग दो माह तक ट्रेनों की आवजाही बंद रही। उसके बाद चल रही विशेष ट्रेनों में सिर्फ आरक्षित टिकट के साथ ही यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाती है। अब कुछ अनारक्षित ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हुआ है, इसलिए चौकसी बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के दौर में सिर्फ दिल्ली मंडल में इस तरह के 29 हजार यात्रियों से 1.178 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार का कहना है कि बे टिकट यात्रियों से न सिर्फ रेलवे को आर्थिक नुकसान होता है बल्कि वैध टिकट लेकर सफर करने वालों

कोरोना काल में लगभग दो माह तक ट्रेनों की आवजाही बंद रही। उसके बाद चल रही विशेष ट्रेनों में सिर्फ आरक्षित टिकट के साथ ही यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाती है।

को भी इनसे परेशानी होती है। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी यह गंभीर मामला है, इसलिए इन्हें रोकना जरूरी है। इसके लिए नियमित जांच के साथ ही विशेष अभियान चलाया जाता है। अगर यात्री बिना टिकट के यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे न्यूनतम 250 रुपये से लेकर एक हजार रुपये जुर्माना या छह माह की कैद या दोनों हो सकता है। इसके साथ ही ट्रेन के शुरुआत वाले स्टेशन से पकड़े जाने वाले स्थान या आगे जिस स्टेशन तक सफर करना है है वहां तक का किराया भी देना पड़ता है।

26 जनवरी की हिंसा में अब तक कितने उपद्रवी हुए गिरफ्तार

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि मामले में अब तक 25 एफआइआर दर्ज की गई है और 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा व केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपॉल ने यह जानकारी मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को दी। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि मामले में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही लालकिले पर सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। केंद्र सरकार की उक्त सूचना को रिकॉर्ड पर लेते हुए मुख्य पीठ ने यह जानने की इच्छा जारी की कि इससे जुड़ा कोई मामला शीर्ष अदालत में लंबित है या दायर किया गया है। पीठ ने इस संबंध में जानकारी देने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने याचिका दायर कर मांग की थी कि कृषि कानून के विरोध की आड़ में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं सभी रास्तों को खाली करने का निर्देश देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। साथ ही उन्होंने हिंसा को रोकने में नाकाम रहने वाले दिल्ली पुलिस आयुक्त को हटाने और लालकिले पर तैनात पुलिस अधिकारियों का दंडित करने की मांग की है। 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रवियों ने दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया था और लालकिले पर पहुंचकर एक झंडा फहरा दिया था।

दिल्ली के 17 लाख लोगों को अगले महीने से मिलेगा घर पर राशन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के 17 लाख गरीबों को उनके घर पर राशन उपलब्ध कराने वाली मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना की अधिसूचना जारी हो गई है। इस योजना की शुरुआत मार्च से होगी। गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट मिलेगा। चावल और चीनी के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि व एक्सपायरी तिथि भी दी जाएगी। सभी प्रकार के सामान गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया सीसीटीवी, जीपीएस व बायोमीट्रिक सिस्टम के तहत पूरी की जाएगी। दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड को सभी सूचना रियल टाइम पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार अतिरिक्त चार्ज लेगी। हालांकि शुल्क अभी तय नहीं किए गए हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली की करीब दो हजार उचित दर दुकानों द्वारा 17 लाख लोगों को चावल, गेहूं व चीनी जैसे सामान मुहैया कराए जाते हैं। चावल व गेहूं को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआइ) से लिया जाता है। चीनी की आपूर्ति खरीदकर की जाती है। बता दें कि राशन लेने के लिए राशनकार्ड धारकों को बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। राशन की सटीक डिलीवरी के लिए सरकार की ओर से सभी राशन की दुकानों पर ईपोस मशीनें लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार गेहूं की पिसाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आटा चक्कियों को चिह्नित किया जाएगा, जहां से लोग पर्ची दिखाकर पिसा हुआ आटा ले सकेंगे। योजना के तहत गरीबों को उचित दर दुकानों तक नहीं जाना पड़ेगा। राशन की दुकानों पर राशन पहुंचने पर लोगों को एसएमएस के जरिये सूचना पहुंचेगी, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनके इलाके की दुकान पर सस्ता राशन पहुंच चुका है।

ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता वीएम सिंह का बड़ा दावा, राकेश टिकैत पर साधा निशाना

नई दिल्ली। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में खुलकर गतिरोध सामने आने लगा है।

26 जनवरी की हिंसा से आहत होकर गाजीपुर से आंदोलन वापस लेने वाले किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने कहा कि हठधर्मिता और नेतगीरी चमकाने के चक्कर में मौजूदा आंदोलन कमजोर हो रहा है।

सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं में चेहरा चमकाने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि उन्हें भी इस कारण दो माह पहले ही किसानों के मोर्चे से बाहर कर दिया गया था तो भी वह किसान एकता के हित में गाजीपुर बार्डर पर डटे रहे। उनके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान थे, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कोई सरोकार भी नहीं था।

प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि टिकैत ने ही ट्रैक्टर रैली को गाजीपुर से दिल्ली की ओर मोड़ा। अब उनका क्या, लेकिन भुगतना तो उन गांव वालों को पड़ रहा है, जिनके अब हिंसा में नाम आ रहे हैं।

उन्होंने कटाक्ष किया कि मात्र वे ही किसान संगठन और नेता नहीं हैं जिन्हें सरकार हमेशा बातचीत की टेबल पर बुला रही है, बल्कि देशभर में सैकड़ों बड़े किसान संगठन हैं, जिनकी बातों को भी सरकार को सुनना चाहिए और बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के 22 किसान संगठनों को लेकर बनी उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा मौजूदा आंदोलन से अलग अपना आंदोलन चलाने जा रही है, जो एक मार्च से शुरू होगा। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा। हर रोज पांच नए किसान क्रमिक अनशन पर बैठेंगे।

इसी तरह रोजाना एक गांव से 150 परिवार प्रधानमंत्री को अपना संदेश पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रमुख मांग एमएसपी की गारंटी वाले कानून की है। यह लागू होता है तो बाकि तीन कृषि कानून रहते भी हैं तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है।

कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक, के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया अगाह

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) के डायरेक्टर ने कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली ही नहीं पूरी देश की जनता को अगाह किया है।

उन्होंने बताया कि यह कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में फिलहाल ज्यादा पता नहीं है। यह नहीं लगता है यह ज्यादा संक्रमित करने वाला है, इससे मौत दर में क्या असर होगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि वैक्सीन इस नए स्ट्रेन को लेकर कितनी कारगर है यह भी अभी पता नहीं है। इसके लिए फिलहाल और ज्यादा रिसर्च की जरूरत होगी। इस पर और अध्ययन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है। इस दौरान हमलोगों को जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए।

संपादकीय

निजी हाथों पर कितना करें भरोसा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दिन क्या अब लद गए हैं? क्या आने वाले समय में देश का भविष्य निजी हाथों में है? या, हम ऐसे किसी मध्यमार्ग का गवाह बन सकते हैं, जिसके हमराह बनकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर देश की तरक्की को साकार कर सकेंगे? ये सवाल इसलिए, क्योंकि बीते बुधवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र की भूमिका की जमकर सराहना की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र जरूरी है, लेकिन निजी क्षेत्र की भूमिका को कमतर नहीं आंका जा सकता। आज भारत मानवता की सेवा इसलिए कर रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र का भी सहयोग मिला। अपने यहां निजी क्षेत्र की अब तक की यात्रा प्रधानमंत्री की बातों को कुछ हद तक सही बताती हैं, लेकिन पूरा सच सिर्फ यही नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आज भी देश में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। कोरोना महामारी का हमारा अनुभव भी इसकी तस्दीक करता है। हमने देखा है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यह किस कदर तत्पर रहा। कोरोना मरीजों की तीमारदारी हो या विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, सरकारी उपक्रम ही आगे रहे। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने ही देश की बुनियाद तैयार की, जबकि निजी क्षेत्र पूंजी की कमी का रोना रोते रहे।

सवाल यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की छवि आज इतनी खराब क्यों हो गई है? आखिर क्यों यह माना जाता है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद लोगों में आरामतलबी बढ़ जाती है? दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र 'क्रोनी कैपिटलिज्म' से जूझ रहा है। इसका अर्थ है कि उद्योगपति सत्तारूढ़ नेताओं और नौकरशाहों से सांठगांठ करके अपना हित साध लेते हैं। जैसे, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में विजय माल्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे और अपनी विमानन सेवा भी शुरू कर चुके थे। नतीजतन, माना यही जाता है कि अपने फायदे के लिए ही उन्होंने किंगफिशर के स्लॉट एअर इंडिया से 10 मिनट पहले तय करवाए, जिसका नुकसान सरकारी विमानन सेवा को उठाना पड़ा। जानी-मानी अर्थशास्त्री जून रॉबिन्सन ने काफी पहले कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ यदि निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र कतई सफल नहीं हो सकता। हमारा अब तक का अनुभव ऐसा ही रहा है। जहां-जहां निजी क्षेत्र का दखल हुआ, वहां-वहां से सार्वजनिक क्षेत्र को बाहर करने की कोशिशें तेज होने लगीं। संभवत- इसीलिए 1993 में वैकल्पिक बजट बनाते समय करीब 20 सांसदों के साथ जब हमारी बैठक हुई, तब पूर्व उद्योग मंत्री अजीत सिंह ने साफ-साफ कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र की तरह चमकदार बनाया जाना चाहिए। उस बैठक में कमोबेश सभी इससे सहमत थे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सांठगांठ करके अपने काम निकालती हैं, जिसका नुकसान अंतत- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उठाना पड़ता है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र को जान-बूझकर महत्वहीन बनाया जाता रहा, जबकि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में यह क्षेत्र कितना आगे है, यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का ही उदाहरण लें। इसने पिछड़े क्षेत्र को भी खूब संवारा है। हरिद्वार में ही जब भेल का संयंत्र लगाया गया, तो रेल पटरियों को खासा मजबूत बनाया गया। न सिर्फ वहां संयंत्र शुरू हुए, बल्कि टाउनशिप भी बसाई गई। कुल मिलाकर, एक पूरा सामाजिक ढांचा तैयार किया गया। निजी क्षेत्र की कंपनियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। पिछली सदी के 90 के दशक के बाद नीतियां इसी तरह से बनाई गईं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां घाटे में जाती रहीं और फिर उनको निजी हाथों में बेचा जाता रहा।

सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों को आरामतलबी से जोड़ने के पीछे भी यही मकसद है। इससे कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाती है। आज भी जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी निजी क्षेत्र के किसी भी मैनेजर से कम काम नहीं करते। सुबह से लेकर देर शाम तक वे मेहनत करते हैं। फिर भी, बाबूगीरी का दाग उन पर थोप दिया गया है। बेशक कई सरकारी संस्थान हैं, जहां काहिली पसरी हुई है। मगर टूटे हुए मनोबल से यदि कर्मचारियों से काम लिया जाए, तो निजी क्षेत्र की कंपनियां भी फायदा नहीं कमा सकतीं। ऐसे में, मध्यमार्ग कहीं बेहतर जान पड़ता है। सार्वजनिक उद्यमों की हमें उन इलाकों में खासतौर से जरूरत है, जहां गरीबी पसरी हुई है। लिहाजा सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता लानी चाहिए और उनको जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। तभी वे सही तरीके से काम कर सकेंगे। रही बात निजी क्षेत्र की, तो इसे भी अवश्य तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन उन जगहों पर, जहां धनाढ्य वर्गों का वास्ता ज्यादा हो। निजी क्षेत्र को खुश करने की परंपरा बंद होनी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक सर्वे के मुताबिक, 90 प्रतिशत दिल्ली वाले प्रतिमाह 25 हजार से भी कम रुपये अपने परिवार पर खर्च करते हैं। इसका साफ मतलब है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्हें निजी बाजार के हवाले नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह बाजार में संतुलन बनाए रखता है और निजी क्षेत्र को मनमानी नहीं करने देता। एम्स यदि कोई ऑपरेशन एक लाख रुपये में करता है, तो निजी अस्पताल चाहकर भी उसके लिए 10 लाख रुपये नहीं मांग सकते। उन्हें अधिक से अधिक तीन-चार लाख में ही उस ऑपरेशन को करना होगा। दूसरे देशों से भी हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। विशेषकर विकसित देशों में बेशक निजी कंपनियों का बोलबाला है, लेकिन इसकी वजह यही है कि वहां गरीबी कम है। अगर हमने अपने यहां निजी क्षेत्र को सब कुछ सौंप दिया, तो हमारे गरीबों का जीना मुहाल हो सकता है। बाजारीकरण की नीतियों ने देश में खासा असमानता बढ़ाई है। एक तरफ हम कम आमदनी वाले देशों में शामिल हैं, तो दूसरी तरह अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर हैं। निजी क्षेत्र को अधिक महत्व यह असमानता और बढ़ती जाएगी।

प्रवीण कुमार सिंह

चीन के चंगुल में न फंसने पाए म्यांमार, अमेरिका को अपनानी होगी दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति

> ऐसे में यह उनके लिए अंतिम विकल्प होगा कि उनका देश फिर से चीन के साये में चला जाए। ऐसे परिदृश्य में भारत को अमेरिका को इसके लिए समझाना चाहिए कि म्यांमार को लेकर प्रतिबंधों के बजाय प्रोत्साहन आधारित दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति अपनाने की दरकार है। अमेरिकियों को भारत और जापान जैसे अपने उन मित्र देशों के साथ अवश्य परामर्श करना चाहिए, जिन्होंने म्यांमार में भारी निवेश किया है और उसके सैन्य नेतृत्व से बढ़िया रिश्ते बनाए हैं। भारत और जापान की नीतियों की धुरी रणनीतिक रूप से इस अहम देश में चीनी प्रभाव की काट करने पर टिकी हुई है।

बीते दिनों म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। इनमें एक प्रश्न यह है कि क्या भारत के इस अहम पड़ोसी देश पर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे और वह फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ जाएगा और वहां वैसे हालात बन जाएंगे जैसे लोकतंत्र की शुरुआत से पहले बने हुए थे? 2010 में भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने म्यांमार के साथ सक्रिय संवाद वाली भारतीय नीति की आलोचना की थी। हालांकि कुछ महीनों के भीतर खुद ओबामा ने भी वैसी ही नीति अपनाई। फिर 2012 में उनका ऐतिहासिक म्यांमार दौरा हुआ। अब म्यांमार पर प्रतिबंधों का साया फिर से मंडरा रहा है तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा?

भारत की 1,643 किमी लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी में 725 किमी लंबी तट रेखा भी है। नई दिल्ली म्यांमार को दक्षिणपूर्व एशिया में अपने द्वार के रूप में भी देखती है। भारत अपनी 'एक्ट ईस्ट नीति' के माध्यम से व्यापक आर्थिक एकीकरण में भी लगा है। म्यांमार और भारत के समक्ष कई साझा खतरे भी हैं। इनमें से एक ताकतवर होते बिगड़ैल चीन से भी है। म्यांमार प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। हालांकि आजादी के बाद से ही यहां सेना को छोड़कर कोई अन्य संस्थान फला-फूला नहीं। यहां विभिन्न मतों और नस्ल वाले लोग रहते हैं। उत्तरी एवं पूर्वोत्तर के इलाकों में नस्लीय अलगाववाद की समस्या भी है। हालांकि सेना ने एक दशक पहले देश में चरणबद्ध रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया, फिर भी पश्चिमी देशों ने सेना के साथ रिश्ते सहज करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए। उन्होंने सिर्फ आंग सान सू की पर ही पूरा दांव लगाया। हालांकि वर्ष

2017 में रोहिंग्या के मसले पर सू की के रवैये से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी।

रोहिंग्या को म्यांमार से बड़ी तादाद में बेदखल करने के वाकये ने 1960 के दशक में म्यांमार से पलायन करने वाले पांच लाख से अधिक भारतीय मूल के लोगों की यादें ताजा करा दी थीं। उस समय म्यांमार सैन्य तानाशाह नेविन की मुट्ठी में था, जिसने 1962 में सत्ता हासिल की। इसके बाद 26 वर्षों तक म्यांमार पूरी दुनिया से कटा रहा। म्यांमार के बर्मीकरण की प्रक्रिया में भारतीयों को वहां से भगाया जा रहा था। नेविन ने भारतीयों को उत्पीड़न का शिकार बनाया। उसने निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया। इसका मकसद संपन्न भारतीयों को विपन्न बनाकर वहां से भागने पर विवश करना था। इसके चलते भारत सरकार को भारतीय मूल के लोगों को वहां से लाने के लिए विमान और नौकाएं भेजनी पड़ीं।

1988 तक आते-आते नेविन की विदाई हो गई। तब तक म्यांमार की गिनती दुनिया के दस सबसे गरीब मुल्कों में होने लगी। अनैतिक इतिहास के बावजूद भारत ने अपने हितों को देखते हुए म्यांमार के सैन्य नेतृत्व के साथ सहयोग बढ़ाया। चार महीने पहले ही भारत ने एक किलो क्लास पनडुब्बी की मरम्मत कराकर उसे म्यांमार को उपहारस्वरूप भेंट किया। यह म्यांमार की पहली पनडुब्बी है। भारत ने पिछले महीने ही 15 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त में म्यांमार को उपलब्ध कराइ हैं। गत वर्ष अक्टूबर में भारतीय सेना प्रमुख और विदेश सचिव ने म्यांमार का दौरा किया था।

यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। ध्यान रहे कि चीन उत्तरी म्यांमार में विद्रोही समूहों को मदद पहुंचाता है। ये विद्रोही भारत के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं। असल में वे भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर सक्रिय हैं। इसे देखते हुए भारत को म्यांमार की सेना के सहयोग की दरकार है।

बीते दिनों हुए सैन्य तख्तापलट ने म्यांमार को लेकर अमेरिकी नीति की एक बड़ी खामी को उजागर कर दिया। वह सैन्य नेतृत्व के साथ कोई कड़ी नहीं जोड़ सका। वास्तव में अमेरिका नवंबर 2019 तक म्यांमार के शीर्ष सैन्य नेतृत्व पर शिकंजा कसे रहा। रोंहग्या मुसलमानों के दमन को नस्लीय सफाया करार देकर उसने दिसंबर 2017 से जनरलों पर वीजा प्रतिबंध लगाए रखने के साथ ही देश पर आर्थिक प्रतिबंध भी जारी रखे। अमेरिका इस सच्चाई को समझने में नाकाम रहा कि म्यांमार में लोकतंत्र को कायम रखने में सेना का सहयोग आवश्यक होगा, अन्यथा वहां सैन्य शासन वापस लौट आएगा। लोकतंत्र को सैन्य नेतृत्व के निरंतर समर्थन के एवज में उसे प्रोत्साहन देने के बजाय अमेरिका उलट व्यवहार ही करता रहा। म्यांमार को लेकर गलत अमेरिकी आकलन ने नए सैन्य शासन के साथ वाशिंगटन के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ी है। अमेरिका अगर फिर से 2012 से पहले वाले प्रतिबंधों के उस दौर में वापस लौटता है जब 25 वर्षों की पश्चिमी सख्ती के कारण म्यांमार को बड़ी हिचक के साथ चीन की गोद में जाकर बैठना पड़ा था तो यह अमेरिका का सबसे खराब दांव होगा। ऐसी कोई भी नीति म्यांमार को लेकर अमेरिका की नाकामी को और उलझाएगी। अमेरिका के नेतृत्व में म्यांमार को अलग-थलग करने की कोशिश चीनी तानाशाह शी चिनफिंग को उस देश में आक्रामक रूप से अपने हितों को पोषित करने का अवसर प्रदान करेगी।

म्यांमार की अति-राष्ट्रवादी सेना चीन पर भरोसा नहीं करती। उसका मानना है कि म्यांमार की सेना और सरकार को साधने के लिए ही चीन वहां अलगाववाद को मदद करता है। म्यांमार के जनरलों को असल में चीन के साथ सू की की बढ़ती नजदीकी भी खटक रही थी। यह नजदीकी तब दिखी भी जब 13 महीने पहले शी ने म्यांमार दौरे के दौरान 33 द्विपक्षीय संबंधों पर हस्ताक्षर किए। यह दो दशकों में किसी चीनी नेता का पहला म्यांमार दौरा था। जनरलों ने चीन पर म्यांमार की निर्भरता घटाने के लिए ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की थी, ताकि वे लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंध बढ़ाकर अपनी विदेश नीति को संतुलन दे सकें। ऐसे में यह उनके लिए अंतिम विकल्प होगा कि उनका देश फिर से चीन के साये में चला जाए। ऐसे परिदृश्य में भारत को अमेरिका को इसके लिए समझाना चाहिए कि म्यांमार को लेकर प्रतिबंधों के बजाय प्रोत्साहन आधारित दूरदर्शी एवं व्यावहारिक रणनीति अपनाने की दरकार है। अमेरिकियों को भारत और जापान जैसे अपने उन मित्र देशों के साथ अवश्य परामर्श करना चाहिए, जिन्होंने म्यांमार में भारी निवेश किया है और उसके सैन्य नेतृत्व से बढ़िया रिश्ते बनाए हैं। भारत और जापान की नीतियों की धुरी रणनीतिक रूप से इस अहम देश में चीनी प्रभाव की काट करने पर टिकी हुई है।

प्रतिष्ठा से बड़ी गरिमा

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में आया दिल्ली की एक अदालत का फैसला उन सभी महिलाओं को हौसला देने वाला है, जो जीवन में किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं या ऐसी आशंका के बीच जी रही हैं। देश में मी-टू आंदोलन का दौर शुरू होने के बाद प्रिया रमानी उन शुरुआती महिलाओं में थीं जिन्होंने कथित उत्पीड़क का नाम लेते हुए अपने उत्पीड़न का ब्योरा दिया। उनके बाद एक-एक कर कई महिला पत्रकारों ने आगे आकर बताया कि उन्हें भी अपने तत्कालीन संपादक अकबर के ऐसे ही कृत्यों का सामना करना पड़ा है। नतीजा यह रहा अकबर को केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। अदालत ने अपने फैसले में प्रिया रमानी को बरी तो किया ही, साथ में ऐसी कई दलीलों को मजबूती से खारिज किया जो बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद मुंह खोलने की हिम्मत करने वाली महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही हैं।

अदालत ने साफ कहा कि प्रतिष्ठा के अधिकार को महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती। यह भी कि पीड़ित महिला घटना के दसियों साल बाद भी जहां ठीक समझे वहां अपनी बात रख सकती है और उसको अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। अदालत का यह फैसला इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मी-टू आंदोलन के बाद अपने देश में भी ऐसे सवाल उठाए जाने लगे थे कि आखिर ये महिलाएं इतने साल चुप क्यों रहीं और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने के बजाय ये सोशल मीडिया पर अपनी बात क्यों कह रही हैं। अदालत ने ठीक ही रेखांकित किया कि ऐसी घटनाएं विक्टिम को अंदर से तोड़ देती हैं। उसका आत्मविश्वास कम कर देती हैं। अक्सर वह खुद को ही दोषी मानती रहती है। इस सबसे उबरने में वक्त लगता है।

बहरहाल, याद रखना जरूरी है कि मी-टू आंदोलन का दूसरा दौर भी समाप्त हो चुका है और वर्कप्लेस पर महिलाओं की स्थिति आज की तारीख में भी उससे किसी मायने में बेहतर नहीं है, जैसी यह मी-टू शुरू होने के समय थी। इसे मी-टू आंदोलन की प्रतिक्रिया कहें या लॉकडाउन का आघात, पर तथ्य यही है कि ऑफिसों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कुछ साल पहले की तुलना में अभी काफी कम हो गई है। वर्कप्लेस पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का यह घटा हुआ अनुपात यौन उत्पीड़न की दृष्टि से उनकी स्थिति को और कमजोर बनाएगा। ऐसे में यह यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वर्कप्लेस पर जैसे बाकी कामकाजी सुविधाएं जुटाई जाती हैं, वैसे ही यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें सुनने वाली एक समिति भी हो और लोग उसके कामकाज के बारे में जानते हों। शिकायत दर्ज कराने और सुलझाने की व्यवस्था जितनी सहज और कारगर होगी, बड़े लोगों की प्रतिष्ठा जाने का डर उतना ही कम होगा।

निरीक्षण की कमी से बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चे असुरक्षित

बाल आश्रय या सुधार गृहों में रह रहे बच्चों के साथ शारीरिक शोषण का यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी ये बच्चे शोषण का शिकार होते हैं। यदि बच्चों को बाल गृह में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वह भी एक प्रकार से उनका शोषण ही है। ये हर बच्चे का हक है कि बाल गृह में उसे सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएं। वर्ष 2017 में जहांगीरपुरी स्थित एक बाल गृह से कुछ बच्चे भाग गए थे। आयोग ने जब बाल गृह का निरीक्षण किया तो वहां पर चौंकाने वाली स्थिति थी। रसोईघर में चूहों की भरमार थी। शौचालय की स्थिति भी बेहद खराब थी। शौचालय में दरवाजा भी नहीं था। बच्चों के लिए साबुन की व्यवस्था तक नहीं थी। बच्चों की शिकायत थी कि उनके साथ शारीरिक शोषण हुआ है।

यह सब कुछ कमेटियों द्वारा उचित निगरानी के अभाव की वजह से हुआ था। इस मामले के बाद दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने त्वरित कार्रवाई भी की थी। ऐसी घटनाएं न हों और बच्चे इन बाल गृहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण करना आवश्यक है। कहीं न कहीं इसमें कमी है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग दो तरह से बच्चों की निगरानी करता है। इसमें पहले वे बच्चे होते हैं जो कुछ समय के लिए बाल गृहों में रहते हैं। दूसरे वे जो लंबे समय के लिए रहते हैं। छोटी अवधि वाले बच्चे अक्सर बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति के होते हैं, जबकि लंबी अवधि वाले वे बच्चे होते हैं, जिनके अभिभावकों का कुछ पता नहीं होता है। यदि किसी बच्चे को बाल गृह में मानसिक या शारीरिक तौर पर कोई कष्ट होता है तो

दो साल पहले तक डीसीपीसीआर ने जिला स्तरीय कमेटियां बनाई थीं जो बाल गृहों में जाकर निरीक्षण करती थीं, अब शायद उस कमेटी को भंग कर दिया गया है। अब एक ही कमेटी है जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग करता है। ये कमेटी ही सभी बाल गृहों में निरीक्षण करती है। जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत संरक्षक कमेटी के पास इतने अधिकार हैं कि यदि बाल गृहों में किसी भी चीज की कमी हो तो सीधे संरक्षक को आरोपी बनाया जा सकता है।

बाल गृहों में बच्चों को कैसे रखना है, इसके लिए सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया बनी हुई है। लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता। कई जगहों पर ये प्रक्रिया तक लोगों को नहीं पता। बाल गृहों को जो एनजीओ संचालित करते हैं, उनकी फाइल सरकार तक जाती है। सरकार द्वारा उनके बाल गृहों का निरीक्षण होता है फिर उनको अनुमोदन मिलता है, लेकिन इस कार्य में पारदर्शिता जरूरी है।

एनजीओ द्वारा संचालित बाल गृहों का तो खास तौर पर समयस मय पर निरीक्षण होना चाहिए। बाल गृहों में जनता को भी सीधा-सीधा स्वयंसेवक के तौर पर जोड़ने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों के छात्र और विभिन्न सरकारी संगठनों के सदस्यों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये स्वयंसेवक समय-समय पर बाल गृहों का निरीक्षण करने के साथ ही बच्चों को परामर्श भी दे सकते हैं।

दिल्ली में मौजूदा समय में दस बाल कल्याण समितियां हैं, जो बेहद कम हैं। दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से हर एसडीएम के क्षेत्र में एक बाल कल्याण समिति होनी चाहिए। ऐसे में कुल 23 और जिला कल्याण समितियां बनाई जानी चाहिए। समितियों की संख्या बढ़ेगी तो निरीक्षण भी अपने आप बढ़ेगा। सरकारी बाल गृहों में संरक्षक की जिम्मेदारी अधिक होती है, इसलिए वहां ज्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन कुछ बाल गृह जो गैरसरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से चल रहे हैं, वहां अक्सर कमी देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण है वहां पर अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कर्मचारी। समय समय पर कर्मचारी बदलते रहने कई तरह की समस्याएं आती हैं, क्योंकि हर एक कर्मचारी का व्यवहार अलग होता है। इनके प्रशिक्षण स्तर में भी कमी रहती है। हर बार कर्मचारी बदलने से बच्चों को उसके साथ मानसिक तौर पर जुड़ने में भी दिक्कत होती है। नहीं होने की वजह से बाल एवं सुधार गृहों में बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। दुर्व्यवहार के ज्यादातर मामलों में वहां के अधिकारी और कर्मचारी ही संलिप्त पाए जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है।

कई राज्यों में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया

> ग्रामीण परिवारों तक जल जीवन मिशन के आशाजनक परिणामों को देखने के बाद ही सरकार ने बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की है, जिससे 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को पाइपलाइन से पीने योग्य पानी की आर्पूति की जाएगी। इस पर 5 साल की अवधि में 2.87 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। वास्तव में आम बजट जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला है।

सपनों को संजोना जितना आसान है, उतना ही कठिन है उन्हें साकार करना, लेकिन विगत छह वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन सपनों को संजोया, उन्हें साकार होते भी हम सब देख रहे हैं- चाहे वह हर घर तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का निर्माण करना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना। समय रहते इन सभी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसी सोच और संकल्प के साथ स्वतंत्रता के 72 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 3.6 लाख करोड़ रु की जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना की घोषणा की, जिसका संकल्प वर्ष 2024 तक देश के 19.04 करोड़ ग्रामीण आवासों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। हर गांव, हर घर तक स्वच्छ जल को पहुंचाना उतना ही कठिन था, जितना एक चींटी का पहाड़ चढ़ना, लेकिन अगर दृढ़ता और संकल्प हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। एक फरवरी को संसद में पेश बजट (2021-22) में भी इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की सोच को साकार करने के लिए पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है।

बचपन में मैंने राजस्थान में माताओं-बहनों को सिर पर मटकी उठाए कोसों दूर चलकर पानी लाते देखा है। तब सोचता था कि इस देश में वह दिन कब आएगा, जब देश के हर घर में नल की व्यवस्था होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन परिस्थितियों को मैं देखता आया हूं, उन्हें दूर करने में मेरा भी योगदान होगा। प्रधानमंत्री ने 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल में जलशक्ति मंत्रालय की नींव रखी और मुझे इस मंत्रालय का दायित्व सौंपा। कोविड-19 महामारी के बावजूद बीते एक वर्ष में हमने देश के 3.34 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिये नल कनेक्शन प्रदान किए हैं, जबकि आजादी के बाद अगस्त 2019 तक 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को ही पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। 1 फरवरी 2021 तक देश के 6.56 करोड़ ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है। प्रतिदिन दो लाख से अधिक घर जल जीवन मिशन से जुड़ रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पहाड़ों पर बने घर हों या फिर हिमाचल प्रदेश में तिब्बत सीमा से महज 10 किमी की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा (15,256 फीट) मतदान केंद्र टशीगंग। राज्य सरकारों के सहयोग से हमारी सरकार ने वहां भी घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम किया है। अब लोगों को मीलों का पैदल सफर तय नहीं करना पड़ता है। टशीगंग जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर घर में जल पहुंचना सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से हमारे विभाग ने इसे कर पाने में सफलता प्राप्त की है। गोवा और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सौ प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। आज देश के 52 जिलों, 660 ब्लॉकों, 39317 ग्राम पंचायतों और 73890 गांवों में हर घर नल से जल के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने इन राज्यों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे समय से पहले ही साकार कर लिया गया है।

बिहार, पुडुचेरी ने 2021, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश ने 2022, अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ ने 2023 और असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल ने 2024 तक सभी ग्रामीण आवासों तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस तरह 2024 तक देश के सभी 19.04 करोड़ ग्रामीण आवास नल कनेक्शन से जुड़ जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत खराब गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर कनेक्शन की जिओ-टैगिंग हो रही है। कनेक्शन को परिवार के मुखिया के आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। जिला स्तर पर मिशन की प्रगति का संकेत देने वाला डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों, सूखा प्रभावित और रेगिस्तानी क्षेत्रों और पानी की खराब गुणवत्ता वाली बस्तियों को वरीयता दी जा रही है। पिछले वर्ष के बजट में जलशक्ति मंत्रालय के लिए 30,478 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जिसमें से 21,500 करोड़ रुपये स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए थे। जल जीवन मिशन के लिए 11,500 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया था। इस बजट में पेयजल के लिए 50,000 करोड़ रुपये और स्वच्छता के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस तरह से शुद्ध पेयजल के लिए बजट आवंटन 450 प्रतिशत तक बढ़ा है। जलशक्ति मंत्रालय के लिए कुल बजट में भी 180 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो जल से जुड़े विषयों पर सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है।

ग्रामीण परिवारों तक जल जीवन मिशन के आशाजनक परिणामों को देखने के बाद ही सरकार ने बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू करने की घोषणा की है, जिससे 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.68 करोड़ शहरी परिवारों को पाइपलाइन से पीने योग्य पानी की आर्पूति की जाएगी। इस पर 5 साल की अवधि में 2.87 लाख करोड़ रुपये का कुल खर्च आएगा। वास्तव में आम बजट जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने वाला है। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने वाले इस बजट का लक्ष्य आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समाधान तलाशना है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

अखिलेश को भाया केमिकल इंजीनियर का इटावा पर रैप, अब सपा पर बनवाएंगे एलबम

इटावा । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के हुनर को पहचाना है। उन्होंने इटावा पर रैप बनाने वाले केमिकल इंजीनियर को समाजवाद पर एलबम बनाने के लिए ऑफर किया है। शहर के ही रहने वाले वाले केमिकल इंजीनियर शिवम वर्मा ने क्षेत्रीय बोली में रैप तैयार करके कंपोज और गाया भी है। उनका बनाया रैप इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इटावा शहर के रहने वाले शिवम वर्मा ने इटावा के प्रमुख स्थानों सहित प्रमुख संस्थानों की खासियत का बखान करते हुए जनवरी 2021 में रैप सांग तैयार किया था और इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया था। इटावा के संत विवेकानंद सीनियर सैकंड्री पब्लिक स्कूल के हॉस्टल के छात्र रहे प्रशांत शाक्य ने वीडियो को फीचर किया है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर इटावा पर बना रैप वायरल हुआ और तारीफें भी मिलना शुरू हो गया। जब यह रैप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुंचा तो उन्हें भी खासा पसंद आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने 21 फरवरी को शिवम को लखनऊ बुलाकर तारीफ की और सम्मान दिया। इसके साथ ही एक किताब भी भेंट की। उन्होंने पार्टी कार्यालय में इटावा पर बने रैप सांग को चलवाकर कार्यकर्ताओं को सुनवाया। उन्होंने शिवम वर्मा से समाजवादी पार्टी के लिए एलबम तैयार करने का ऑफर किया। शिवम ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया और वह समाजवाद के नाम से नया एलबम बनाएंगे।

शहर के मोहल्ला करमगंज के रहने वाले शिवम वर्मा ने बताया कि इंटरमीडिएट करने के बाद वह हरियाणा के फरीदाबाद में प्राइवेट कंपनी में जॉब करने चले गये थे। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है उसके बाद एमबीए भी किया। उन्होंने बताया कि पिता कवि थे, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने गीत लिखना शुरू किया था। फीरोजाबाद जनपद के एक प्रोडक्शन हाउस ने क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल की वजह से उनका काफी अपमान किया था, उसके बाद उन्होंने तय किया था कि वह इटावा की भाषा में ही रैप सांग तैयार करेंगे।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर अब यूपी में नहीं होंगे आरटीओ से जुड़े काम, नियम न मानने पर होगी कार्रवाई

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी होगी, उनके आरटीओ से जुड़े काम भी नहीं हो पाएंगे। यानी ऐसे वाहनों का स्थानांतरण, पता परिवर्तन और फिटनेस प्रमाण पत्र आदि नहीं मिल पाएंगे। नियम न मानने वाले आरटीओ व एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव भी हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने परिवहन आयुक्त को भेजे आदेश में कहा है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत एचएसआरपी लगाया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लगाने से कई फायदे भी हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा है कि एचएसआरपी लगाए जाने के बाद ई-चालान प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मोटरयान को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब उसमें एचएसआरपी लगी हो। निजी, कॉमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के स्थानांतरण, पता परिवर्तन, इंश्योरेंस, फिटनेश प्रमाण पत्र के अलावा सभी कार्यो पर रोक लगा दी गई। कार्य कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।

नंबर प्लेट बुकिंग की पर्ची भी होगी मान्य = उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एचएसआरपी की ऑनलाइन बुकिंग कर जो रसीद मिलती है उसे भी आरटीओ में काम कराने के लिए मान्य कर दिया गया है। यानी रसीद दिखाकर आरटीओ से जुड़े काम हो सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि एचएसआरपी बुकिंग के बाद वाहन स्वामी को प्लेट लगवाने के लिए 10 से 15 दिन बाद का समय मिलता है। प्रमुख सचिव ने बताया कि नंबर प्लेट की बुकिंग होने पर यह मान लिया जाएगा कि भविष्य में एचएसआरपी वाहन पर लग जाएगी।

मुजफ्फरपुर में शराब धंधेबाजों ने खोले कई राज, अब मोबाइल से खुल रहा शराब का खेल

मुजफ्फरपुर । विशेष पुलिस टीम के हत्थे चढ़े चार शराब धंधेबाजों ने पूछताछ में जिले के अलावा उत्तर बिहार में सक्रिय कई के नाम उजागर किए। इन आरोपितों का हरियाणा व अन्य प्रदेशों के शराब सिंडिकेट के धंधेबाजों से तार जुड़े हैं। इनके पास से जब्त मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगालकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कॉल डिटेल्स में अन्य धंधेबाजों के नंबर के बारे में भी टीम को पता चला है। इसके आधार पर विशेष टीम ने मंगलवार की देर रात कई जगहों पर छापेमारी की। लेकिन और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बता दें कि विशेष टीम ने करजा थाना क्षेत्र के रसुलपुर इलाके में छापेमारी कर 49 लाख 98 हजार रुपये के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया था। इनके ठिकाने से हथियार भी जब्त किए गए थे।

एसएसपी जयंत कांत ने कहा कि निशानदेही पर कई जगहों पर कार्रवाई चल रही है। बताते चले कि छापेमारी में कमलेश ठाकुर के पुत्र राहुल के घर से 49.98 लाख रुपये, चार लाख का चेक व एक गोली बरामद की गई थी। लेकिन ये दोनों गिरफ्त में नहीं आ सके थे। इसके बाद वीरेंद्र ठाकुर के घर पर छापेमारी की गई थी। इसमें वीरेंद्र व उसके पुत्र राहुल कुमार को पकड़ा गया था। उसके घर से एक राइफल, दो पिस्टल, तीन मैगजीन, दो गोली व 26 लीटर शराब जब्त की गई थी। पूछताछ में पता चला कि इन सभी का तार हथियार तस्कर से भी जुड़े है। इसके लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसके अलावा ठिकाने से अन्य दो आरोपित सरैया पोखरैरा के अभ्यानंद शर्मा उर्फ टिंकू शर्मा व सरैया दुबियाही के आलोक रंजन उर्फ भोला को पकड़ा गया था। कहा गया कि इन सभी की पूर्व की गतिविधि के बारे में भी रिकार्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि नकेल कसने की कवायद की जा सके।

बिहार प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़ गए कांग्रेस कार्यकर्ता, धक्का-मुक्की और हाथापाई

कटिहार । कटिहार किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली थी। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी यहां पहुंचे। इसी सिलसिले में पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही थी। इसी दौरान जिलाध्यक्ष के खिलाफ विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच जिलाध्यक्ष के समर्थक भी वहां हंगामा करने लगे। दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। विरोधी गुट के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग की।

यहां पदयात्रा और बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास भी आए थे। उन्हीं की अगुवाई में कृषि कानून के विरोध में सत्याग्रह पदयात्रा निकाली जानी थी। वे भी यहां आ गए थे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता इकट्ठे ही हुए थे कि कांग्रेस के कटिहार जिलाध्यक्ष प्रेम राय के विरोधी गुट ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद जिलाध्यक्ष के समर्थक भी वहां कूद गए। दोनों के बीच धक्का-मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। हंगामा उस समय और उग्र हो गया, जब एक गुट ने मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर उनके अनुपस्थित में कटाक्ष शुरू कर दी। विधायक मनोहर प्रसाद वहां नहीं आए थे।

यूपी में कोरोना से संक्रमित 108 नए रोगी मिले, सीएम योगी का निर्देश- संकट अभी टला नहीं, बरतें सर्तकता

लखनऊ । देश में जहां महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दोबारा कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं यूपी में लगातार संक्रमण कम हो रहा है। बीते 15 दिनों में 32 फीसद कोरोना रोगी कम हुए हैं। नौ फरवरी को प्रदेश में 3,306 एक्टिव केस थे और अब यह घटकर 2,268 रह गए हैं। यानी 1,038 मरीज कम हुए हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अभी पूरी सर्तकता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में बीते चौबीस घंटों को दौरान 1.23 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो 108 नए रोगी मिले। वहीं, 24 घंटे में 202 मरीज स्वस्थ भी हुए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए अभी पूरी सर्तकता बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम में डीएम और सीएमओ दो बार बैठक करें। सीएम योगी ने कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कोविड टेस्टिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग पर पूरा जोर देने के निर्देश दिए हैं। कार्यालयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क पूरी तरह सक्रिय रहें और अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। लोगों को दो गज की शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करने और सैनिटाइजेशन का काम समय-समय पर कराए जाने के भी निर्देश दिए।

98.17 फीसद रिकवरी रेट = यूपी में बीते चौबीस घंटों को दौरान 1.23 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो 108 नए रोगी मिले। यानी जितने लोगों की जांच की गई उसमें से केवल 0.08 प्रतिशत ही संक्रमित पाए गए। वहीं, 24 घंटे में 202 मरीज स्वस्थ हुए। अभी तक कुल 6.02 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 5.91 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 98.17 फीसद हो गया है।

दो और मरीजों की हुई मौत = कोरोना संक्रमण से दो और लोगों की मौत हुई और अभी तक 8,718 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। अब एक्टिव केस 2,268 हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 43 जिलों में एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला। महाराजगंज में अब कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है। 25 जिलों में इस समय 10 से कम रोगी हैं। प्रदेश में अभी तक तीन करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। संक्रमित मिले रोगियों में से 10 फीसद की होगी जीनोम सिक्वेंसिंग = देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व पंजाब सहित पांच राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार बचाव के कड़े उपाय कर रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बावजूद वह किसी भी तरह की ढ़िलाई नहीं बरतना चाहती। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों में से 10 प्रतिशत की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम सिक्वेंसिंग के माध्यम से नए स्ट्रेन का पता चलता है। प्रदेश में बीते दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी मध्य तक नए स्ट्रेन से संक्रमित 17 मरीज मिले थे, लेकिन बेहतर कोविड-19 प्रबंधन के चलते मरीज स्वस्थ हो गए और तब से कोई नया रोगी भी सामने नहीं आया।

केजीएमयू व आइजीआइबी लैब भेजे जाएंगे सैंपल = जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव मरीजों का सैंपल राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) और जरूरत पड़ने पर नई दिल्ली में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (आइजीआइबी) की लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 108 रोगी मिले यानी इसमें से 11 संक्रमितों की जीनोम सिक्वेंसिंग होगी। ऐसे ही प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों में से 10 फीसद की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाएगी। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट है।

बैतालपुर इंडियन आयल डिपो में टैंकर में लगी आग, चालक व खलासी झुलसे

गोरखपुर । देवरिया जनपद के बैतालपुर स्थित इंडियन आयल डिपो में तेल लेने गए टैंकर के चेंबर में बुधवार की सुबह आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान चालक जय प्रकाश एवं खलासी वशिष्ठ दुबे झुलस गए। अग्निशमन व डिपो कर्मचारियों के प्रयास के प्रयास से कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।

सुबह नौ बजे तेल डिपो में टैंकर में तेल लेने के लिए गया था। अचानक टैंकर के चेंबर में आग पकड़ लिया। आग को बुझाने के दौरान चालक व खलासी झुलस गए। डिपो में आग लगने की सूचना पर देवरिया से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी चार फायर टैंकर के साथ पहुंचे। डिपो के अंदर अफरा-तफरी की स्थिति के चलते कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिसकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

बैतालपुर डिपो में आग की सूचना मिलने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। इमरजेंसी कक्ष को खाली करा लिया गया है। इमरजेंसी में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में भेज दिया गया है। डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी में पहुंच गई है। वार्ड ब्वाय और अन्य कर्मचारियों को बुलाया गया है। डा. आरके श्रीवास्तव, डॉक्टर एनके पांडेय इमरजेंसी के चिकित्सक कक्ष में पहुंच गए। आग लगने के बाद कर्मचारियों ने डिपो प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि डिपो में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी आग लगने के बाद आग बुझाने में जुटे हुए थे, जबकि अधिकारी सबसे पहले कैंपस से फरार हो गए। कोई विशेष सुविधा भी नहीं दी गई है। कर्मचारी झुलस गया, लेकिन उसे देखने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया।

नहीं बजा सायरन- डिपो में अग्निशमन यंत्र है। कहीं भी कोई आग लगे तो सायरन बजाया जाता है, लेकिन आग लगने के बाद यहां लगा सायरन नहीं बजाया गया। साथ ही अधिकारी आग बुझने के बाद कैंपस में पहुंचे।

रांची के मॉल में 3 महिलाएं कर रही थीं गंदा काम, सीसीटीवी फुटेज में दिखा इनका कारनामा...

रांची । झारखंड की राजधानी रांची के एक मॉल में तीन महिलाएं गलत काम करने की नीयत से घुसीं। यसीसीटीवी फुटेज में इन महिलाओं का कारनामा रिकॉर्ड हो गया। पुलिस अब इन महिलाओं को पकड़ने के लिए जांच-तलाशी कर रही है। बताया गया कि इन महिलाओं का गिरोह चोरी-स्नैचिंग में संलिप्त हैं। ये काम-काजी महिलाओं को अपना निशाना बनाती हैं।

रांची में सक्रिय महिलाओं के चोर गिरोह मॉल और बड़े प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदात कर रहे हैं। मंगलवार को लालपुर थाने के न्यूक्लियस मॉल में ऐसी तीन महिलाएं एक महिला का पर्स लेकर चलते बनीं। रांची के पिस्का मोड़ काजू बगान की रहने वाली पीड़िता पूनम कुमारी खरीदारी के लिए यहां पहुंची थीं। इन्हें चकमा देकर महिला चोर गिरोह ने उनका पर्स उड़ा लिया। पर्स में रुपये और जरूरी कागजात थे।

सामान खरीदने के बाद जब महिला पूनम कुमारी ने पेमेंट के लिए पर्स निकाला, तो बैग से उनका पर्स गायब था। महिला के शोर मचाने के बाद मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे गए। यहां तीन महिलाएं उनके पीछे पड़ीं दिख रही हैं। जो मौका देखकर उन्हें चकमा दे गई और उनके बैग से उनका पर्स निकाल लिया।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और महिला के बयान पर एफआइआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है। ऐसी महिलाओं को पकड़ने के लिए जांच-तलाशी की जा रही है।

सदर थाने की पुलिस ने कोकर के एक घर में चोरी करने के आरोप में नाबालिग समेत तीन महिलाओं को दबोचा है। इनमेंशांति देवी, पूजा कुमारी व एक नाबालिग शामिल है। दो महिलाओं को पुलिस ने मंगलवार को जेल भेजा, जबकि एक नाबालिग को रिमांड होम भेजा है। जानकारी के अनुसार कोकर आदर्श नगर की रहने वाली सुनीता देवी के मकान में बीते सोमवार को तीन महिलाएं उनके घर में घुसीं।

ये महिलाएं घर से कुछ सामान चोरी कर भाग रही थी। इसी दौरान सुनीता और उनके परिजनों ने तीनो को पकड़ लिया। उसकी धुनाई करने के बाद सदर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया।

पूछताछ में महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वह बोकारो की रहने वाली है। गुलगुलिया गैंग की सदस्य है।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध

लखनऊ । पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि यूपी सरकार गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में जघन्य अपराध के दस केस चल रहे हैं। सरकार ने आग्रह किया कि मुख्तार को यूपी जेल भेजा जाए और उससे संबंधित मामला भी प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की मांग पर अगली सुनवाई मंगलवार यानी दो मार्च तक के लिए टाल दी है।

यूपी के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी ट्रांसफर करने की सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिक पर बुधवार को सुनवाई हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना एमपी-एमएलए कोर्ट की अनुमति के पंजाब पुलिस को सौंपा था। अपराधी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई बार पेशी वारंट जारी किए गए, लेकिन पांजाब की रोपड़ जेल के अधिकारी उसे बीमार बताते रहे हैं। लंबे समय से पुलिस उसे यूपी लाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार ने हलफनामे में कहा कि मोहाली मामले में दो साल से चार्जशीट जमा नहीं हुई है, फिर भी मुख्तार अंसारी जमानत नहीं ले रहा है, इससे मिलीभगत साफ दिख रही है। सरकार ने आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के हित में अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे और मुख्तार को वापस यूपी भेजने का आदेश दे। यूपी सरकार ने कहा कि मोहाली में दर्ज केस भी प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया जाए। मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी की मांग पर न्यायाधीश ने बिना कोई फैसला दिए अगली सुनवाई को दो मार्च तक के लिए टाल दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित करने का विरोध किये जाने पर कड़ा एतराज जताया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पंजाब सरकार एक गैंगस्टर का समर्थन कर रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराध दर्ज हैं और सुनवाई कोर्ट में लंबित है। मेहता ने कहा कि पंजाब सरकार अंसारी का इतना ज्यादा समर्थन कैसे कर सकती। ये गंभीर मसला है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बता दें कि मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश लाने की पुलिस की अब तक हर तरकीब फेल रही है। यूपी सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया, लेकिन वहां भी अब तक असफलता ही हाथ लगी। पंजाब सरकार ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब भी यूपी पुलिस व सरकार मुख्तार को यूपी लाने की जुगत में लगी हुई है। अब तक इस सिलसिले में दो बार गाजीपुर पुलिस पंजाब जा चुकी है।

सदन में सीएम नीतीश का विपक्ष को करारा जवाब, तेजस्वी को बोले- बैठ जाओ, आपको गोद में खेलाया है

पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पूरे विपक्ष पर सदन में जमकर पलटवार किया। मंगलवार (23 फरवरी) को बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण पर विमर्श के दौरान तेजस्वी के बार-बार टोकाटोकी करने पर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि हम क्या गोदी में नहीं उठाए हैं, चुपचाप बैठो। तुम्हें गोद में खेलाया है। उन्होंने तेजस्वी के तमाम आरोपों सहित पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया है।

अच्छा लगता है आपका बोलना

मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान जब तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए तो उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सदन में मैंने आपकी सारी बातें सुनीं। अब मेरी भी सुन लीजिए। आगे आपको ही फायदा देगा। मैं जब केंद्र में मंत्री था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी से जो भी सीखा, वह आज भी मेरे काम आ रहा है। मेरे भी मार्गदर्शन में आपने बतौर डिप्टी सीएम एक साल आठ महीने काम किया। उस वक्त का फायदा भी लोगों को बताइए । मैं तो चाहूंगा कि आपको मौका मिले और आप बोलें। मुझे अच्छा लगता है, जब आप बोलते हैं।

कांग्रेस को करारा जवाब

आज सदन में सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष का करारा जवाब दिया। उन्होंने शराबबंदी हटाए जाने की मांग पर कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का सदस्यता फॉर्म दिखाया। कहा, इसमें सदस्यों से शपथ ली जाती है कि वे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते। यह तो बापू का ही सिद्धांत था। आप एक तरफ तो सदस्यों से वचन लेते हैं कि मैं दारू से दूर रहता हूं, दूसरी ओर शराबबंदी हटाने और शराब की दुकान खुलवाकर दारू के नजदीक जाना चाहते हैं।

एआइएमआइएम की मांग खारिज- मुख्यमंत्री ने एआइएमआइएम के विधायकों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने एआइएमआइएम की मांग के अनुसार पूर्णिया को बिहार की राजधानी बनाने से इंकार किया।

नेताओं की बगावत के बाद चिराग पासवान ने बनाया दलित-सवर्ण गठजोड़, राजू तिवारी बने कार्यकारी अध्यक्ष

पटना । लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष चिराग पासवान अब दलित-सवर्ण गठजोड़ बनाकर प्रदेश में अपनी राजनीति को नया रंग देने की कोशिश में हैं। इसकी बानगी है कि उन्होंने राजू तिवारी को प्रदेश लोजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। सांसद प्रिंस राज पहले की तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इसी के साथ चिराग ने अपने करीबी पार्टी प्रवक्ता संजय पासवान को प्रदेश इकाई का प्रधान महासचिव बनाया है।

प्रदेश कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों एवं जिलाध्यक्षों का होगा एलान

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी, प्रकोष्ठों एवं जिलाध्यक्षों का एलान होगा। दलित और सवर्ण वर्ग के अलावा पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद चिराग ने प्रदेश संगठन से लेकर निचले स्तर तक की तमाम इकाइयों और प्रकोष्ठों को भंग कर चुके हैं। बहरहाल राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कई नेताओं में नाराजगी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो फिलहाल खुले तौर पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की मानें तो अब सिर्फ प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार है।

208 नेताओं ने थामा था जदयू का दामन - उल्लेखनीय है कि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के 208 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ सामूहिक रूप से जनता दल युनाइटेड (जदयू) का दामन थामा है। विधान परिषद में पार्टी की एकमात्र सदन नूतन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पाले में जा चुकी हैं। वे राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज सिंह बबलू की पत्नी हैं, जो छातापुर से भाजपा के विधायक हैं। अपने एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को भी लेकर पार्टी इत्मीनान में नहीं, क्योंकि उन पर भी दूसरे दलों द्वारा डोरे डाले जाने की सूचनाएं मिल रही हैं।

आधी-अधूरी जानकारी पर मंत्री नाराज, पिथौरागढ़ और टिहरी के डीएचओ को लगाई फटकार

देहरादून । औद्यानिकी के विकास के लिए आवंटित बजट को खर्च करने के मामले में तमाम जिलों में गति धीमी है तो कई विषयों पर अधिकारियों में जानकारी का भी अभाव है। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने सोमवार को उद्यान विभाग के कार्यों की समीक्षा की तो उसमें यह बात सामने आई। कैबिनेट मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पिथौरागढ़ के डीएचओ को सिंचित क्षेत्र की जानकारी न होने और राज्य सेक्टर में कम खर्च पर टिहरी के डीएचओ को फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक कहा कि अधिकारी बजट का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित करें। इसमें कोताही बरतने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री उनियाल ने केंद्र, राज्य व जिला सेक्टर की उद्यान से संबंधित सभी योजनाओं की बिंदुवार जानकारी ली। बैठक से सभी जिलों के जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) समेत कई अधिकारी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मोर ड्राप-मोर क्राप समेत अन्य योजनाओं के बजट का जल्द सदुपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य एवं जिला सेक्टर की योजनाओं का बजट भी 31 मार्च तक हर हाल में खर्च करने पर जोर दिया। उन्होंने आइएमए विलेज योजना में शामिल गांवों में टपक सिंचाई व घेरबाड़ से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को वह फिर से विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों की नीति का करें अध्ययन- कैबिनेट मंत्री उनियाल के मुताबिक बैठक में राज्य की प्रसंस्करण नीति के संबंध में भी चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नीति का मसौदा तैयार करने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों की नीति का अध्ययन भी कर लिया जाए।

गुप्ता को नर्सरी विकास का जिम्मा- उद्यान मंत्री ने औद्यानिकी विकास के लिए राज्य की जरूरत के अनुसार पैरेंटियल मटीरियल यहीं तैयार करने पर जोर दिया। इस कड़ी में उन्होंने विभाग के संयुक्त निदेशक बृजेश गुप्ता को राज्य की सभी नर्सरियों के विकास का जिम्मा सौंपने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए।

दून में जल्द बनेगा परिषद का मुख्यालय- कृषि मंत्री उनियाल ने सोमवार को उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि दून में परिषद का मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय पहले लिया जा चुका है। तब राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया था। बाद में इस एजेंसी को नए कार्य न देने का फैसला लिया गया।

इस मार्गदर्शक सिद्धांत को शासन स्तर पर गलत परिभाषित किए जाने से यह कार्य बाधित हो गया था। उन्होंने निर्देश दिए कि इस त्रुटि को सुधारते हुए अविलंब धनराशि जारी की जाए, ताकि दून के भाऊवाला में परिषद के मुख्यालय भवन का निर्माण हो सके। फिलहाल परिषद मुख्यालय को पंतनगर विवि के हल्दी परिसर से पटवा डांगर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया।

तेंदूपत्ता संग्रहन व विक्रय का कार्य करेगी महा ग्रामसभा रोरिया

पदाधिकारियों ने पत्रकारवार्ता में दी जानकारी

जबलपुर (एजेंसी)।

जिले के कुण्डम विकासखंड की 15 ग्रामसभाओं का विधिवत महासंघ महा ग्रामसभा रोरिया बनाकर वन अधिकार अधिनियमों के अनुसार लघुवनोपज का विक्रय किया जायेगा। इसके अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहन और विक्रय का कार्य करेगी महा ग्रामसभा रोरिया करेगी। उपरोक्त जानकारी महा ग्रामसभा रोरिया पदाधिकारियों ने मंगलवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में दी।

पत्रकारवार्ता में संगठन अध्यक्ष हुब्बीलाल आर्मे, सचिव लालाराम तेकाम, आनोद सिंह मसराम ने बताया कि वन अधिकारी अधिनियमों के अनुसार जीविका की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघुवनोपज के विक्रय का प्रयोग कर सकते हैं। नियमानुसार ग्रामसभाओं के महासंघ लघुवनोपज का विक्रय करने अपनी परमिट प्रणाली विकसित कर सकती है। वन संसाधनों पर अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं के क्षेत्र का तेंदूपत्ता संग्रहन और विक्रय का कार्य ग्रामसभाओं के द्वारा करने के प्रावधान अनुसार किया जा सकता है। वन संसाधनो पर अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं के क्षेत्र का तेंदूपत्ता संग्रहन और विक्रय का कार्य ग्रामसभाओं के महासंघ महा ग्रामसभा रोरिया द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर इस वर्ष करने जा रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कोमल सिंह मरावी सहित अन्य मौजूद रहे।

चीन की चालबाजी को जानता है भारत, संबंध ठीक करने को ड्रैगन को करना है अभी बहुत कुछ

नई दिल्ली । भारत और चीन के बीच भले ही लद्दाख में पैंगोंग इलाकों से डिसइंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मगर चालाक चीन कब चालबाजी दिखा दे, इसके लिए भारत को हमेशा सतर्क रहना होगा। भारत-चीन मामलों से जुड़े लोगों ने कहा कि पैंगोंग इलाकों से दोनों सेनाओं का पीछे हटना महज एक प्रक्रिया की शुरुआत है, चीन को द्वीपक्षीय संबंधों को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में बहाल करने के लिए अभी और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

नाम न जाहिर होने देने की शर्त पर इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि सीमा पर तनाव को कम करने के लिए द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय स्तर पर चीन का अगला कदम क्या होगा, इसे बारीकी से देखा जाएगा। मामले से जुड़े लोगों में से एक ने कहा, ट्रेन पटरी से उतर गई थी। हमने इसे वापस पटरियों पर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चीजें कहां तक जाती हैं। मामले से जुड़े लोगों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर से भारतीय और चीनी सेना की हालिया वापसी (डिसइंगेजमेंट) को एक अच्छी शुरुआत बताया, लेकिन आगाह किया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई अन्य टकराव के अन्य बिंदुओं पर विवाद को हल करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

एक अधिकारी ने कहा, भारत और चीन के बीच में बहुत सी चीजें गलत हो गई हैं और चीजों को सही करने का काम अब शुरू हो गया है। आगे बढ़ने की बात करने से पहले हमें चीजों को वापस ट्रैक पर लाना होगा। बता दें कि पैंगोंग झील में डिसइंगेजमेंट के पूरा होने के बाद 20 फरवरी को भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता आयोजित हुई थी, जिसमें टकराव के अन्य बिंदू जैसे गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेपसांग इलाकों से सेना को पीछे हटने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, मगर अब तक इस दिशा में कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है।

10वें दौर की सैन्य बैठक के जारी किए गए एक संयुक्त बयान में पैंगोंग झील से दोनों सेनाओं की वापसी को एक अहम कदम बताया गया था और कहा गया कि दोनों पक्ष स्थिर और क्रमबद्ध तरीके से बाकी के बचे मुद्दों के पारस्परिक स्वीकार्य समाधान के लिए बातचीत जारी रखेंगे। बता दें कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेपसांग इलाकों से भी चीनी सेना को पीछे हटना होगा, तभी जाकर स्थिति सामान्य हो सकती है।

हालांकि, इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि चीनी पक्ष के साथ बातचीत का अगला दौर कब होगा, राजनयिक या सैन्य स्तर वार्ता होगी, तत्काल इसके संकेत नहीं दिखते। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि 2021 के लिए ब्रिक्स समूह की भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने वाले चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देना चाहिए। बता दें कि ब्रिक्स की मेजबानी के लिए चीन ने भारत का समर्थन किया है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी खत्म करने में अमेरिका के लिए कितना मददगार होगा भारत

नई दिल्ली । अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन अपनी विदेश एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति की समीक्षा कर रहा है, ऐसे में विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों का कहना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और सेंटर फॉर चाइना एनैलिसिस एंड स्ट्रैटजी के अध्यक्ष जयदेव राणाडे समेत विशेषज्ञों ने यहां थिंक टैंक द हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित डिजिटल चर्चा में यह बात की।

मेनन और राणाडे ने अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया। मेनन ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होते रहेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, चीन, हिंद प्रशांत और समुद्री सुरक्षा पर रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने देश में हो रहे बदलाव के लिहाज से अमेरिका को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है बल्कि वह उसे दुनिया की एकमात्र महाशक्ति भी समझता ह। इसके अलावा मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के साझा रणनीतिक दृष्टिकोण हैं। मेनन ने कहा कि अमेरिका, कारोबार के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश है और हम जानते हैं कि मतभेद होने पर उन्हें कैसे सुलझाया जाए।

चीन में भारत के पूर्व राजदूत मेनन ने कहा कि 2012 से दक्षिण एशिया में चीन की सक्रिय मौजूदगी रही है और वह पाकिस्तान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता रखता है। नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की आंतरिक राजनीति में भी वह भूमिका निभा रहा है और हिंद महासागर में उसने सैन्य दखल बढ़ाया है, जो भारत के लिए समस्या पैदा करने वाला है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके मेनन ने कहा, चीन भारत की बढ़ती साख और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सीट और एनएसजी जैसे मुद्दों पर भारत का विरोध करता रहा है।

इस अवसर पर राणाडे ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का लक्ष्य सबसे पहले खुद को एशिया में या हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख ताकतवर देश के तौर पर स्थापित करना है और फिर अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना है। उन्होने कहा कि चीन की इस मंशा के रास्ते में भारत खड़ा है।

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की समस्याओं के निराकरण की मांग

जबलपुर (एजेंसी)।

मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि प्रदेश के लगभग सभी विभागों के रिटार्यड (सेवानिवृत्ति) कर्मचारियों को रिटार्यडमेन्ट या सेवानिवृत्ति के दिन या बाद में भी सभी प्रकार के देयकों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता, अपितु कई कर्मचारियों को तो पी.पी.ओ भी नहीं मिल पाता है जिससे सेवानिवृत्त या रिटार्यड होने के बाद इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ता है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता।

संघ ने बताया कि रिटार्यड/सेवानिवृत्त होने के पश्चात कर्मचारियों का समय पर पेंशन निर्धारण नहीं हो पाता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही जो कर्मचारी अपने विभागों में पूंर्ण ईमानदारी और निष्ठापूर्ण तरीके से अपनी सेवा 30-35 वर्षो तक विभाग को देता है उसे रिटार्यड/सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ही पैसों या अपने ही देयकों को प्राप्त करने के लिए दलालों के चक्कर काटना पड़ता है, दफतरों में सक्रिय दलाल उनका आर्थिक शोषण करते हैं, वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कार्यालयों के अधिकारी भी असहयोगात्मक रवैया रिटार्यड कर्मचारियों के साथ करते है और रिटार्यड कर्मचारी इस दफतर से उस दफ तर के चक्कर काटने मजबूर हो जाता है, पर उनकी कोई नहीं सुनता अन्ततः उनसे वसूली का कार्य प्रारम्भ हो जाता हैं, ये सेवानिवृत्त/रिटार्यड कर्मचारियों के साथ अन्याय है संघ इसका पुरजोर विरोध करता करते हुए कलेक्टर से मांग करता है कि हर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सक्त हिदायत दी जाए की वे अपने विभागों के रिटार्यड कर्मियों के देयकों का समय पर भुगतान करें। संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया, रॉबर्ट मार्टिन, जियाउर्रहीम, मीनूकांत शर्मा, अशोक परस्ते, एनोज विक्टर, शहीर मुमताज़, दिनेश गौड़, सुनील स्टीफन, हेमंत ठाकरे, अनूप कुमार, प्रकाश मिश्रा, राजेश सहारिया, गोपीशाह, विनोद सिंह, गुडविन चार्ल्स, गिरीशकांत मिश्रा, आशाराम झारिया, वसुद्दीन, अजय मिश्रा, शरीफ असांरी, चैतन्य कुषरे, आशीष कोरी आदि ने कलेक्टर से मांग की है कि कर्मचारयों को रिटार्यड/सेवानिवृत्त होने के पश्चात अपने ही देयकों के लाभ पाने से वंचित न रहना पड़े उन्हे सभी प्रकार के लाभ समय पर मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- हिन्दू महिला पिता के परिवार को दे सकती है अपनी संपत्ति

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि हिन्दू महिला के पिता की ओर से आए लोगों को उसकी संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। ऐसे परिजनों को परिवार से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जा सकता, हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1.डी के दायरे में आएंगे और संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे।

फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिन्दू उत्तराधिकार कानून, 1956 की धारा 15.1.डी के तहत उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13.1.डी को पढ़ने से साफ जाहिर है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना गया है, जो संपत्ति को ले सकते हैं। लेकिन, जब महिला के पिता की ओर से आए उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाता है, जो संपत्ति को हासिल कर सकते हैं तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वे परिवार के लिए अजनबी हैं और महिला के परिवार के सदस्य नहीं हैं।

क्या है मामला- कोर्ट ने यह व्यवस्था एक ऐसे मामले में दी, जिसमें एक महिला जग्नो को उसके पति की संपत्ति मिली थी। पति की 1953 में मौत हो गई थी। उसको कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिला। उत्तराधिकार कानून, 1956 बनने के बाद धारा 14 के अनुसार, पत्नी संपत्ति की एकमात्र पूर्ण वारिस हो गई।

इसके बाद जग्नो ने इस संपत्ति के लिए एक एग्रीमेंट किया और संपत्ति अपने भाई के पुत्रों के नाम कर दी। इसके बाद उनके भाई के बेटों ने 1991 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया कि उन्हें मिली संपत्ति का स्वामित्व उनके पक्ष में घोषित किया जाए। जग्नो ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और अपनी संस्तुति दे दी।

भाजपा सांसद की उद्धव ठाकरे को सलाह- महाराष्ट्र में कोरोना पर नहीं हो रहा कंट्रोल तो अमित शाह से लें मदद

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद लेने की सलाह दी है। शेट्टी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ÷यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र को कोविड-19 के प्रसार का सामना करना पड़ रहा है। यह दिल्ली की तरह एक शहर है, जिसमें महामारी पर नियंत्रण करने में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान है।

बीजेपी सांसद शेट्टी ने आगे कहा, ÷उद्धव ठाकरे को केंद्र सरकार से तुरंत मदद लेनी चाहिए। लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए सभी राजनीतिक मतभेद को एक तरफ रख कर अमित शाह के समर्थन लेनी चाहिए। जनता के हित में जो कुछ भी करना चाहिए वह कर सकते हैं। यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अमरावती शहर में एक सप्ताल के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी लोगों को चेतावनी दी कि अगर वे महामारी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते तो राज्य में फिर एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है।

गोपाल शेट्टी ने राज्य सरकार को ऐसी गंभीर स्थिति में राजनीति के बजाय कुछ ठोस कदम उठाने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने पर भी जोर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि वैक्सीन के दायरे में भी वृद्धि की जानी चाहिए, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां संख्या बढ़ रही हैं।

कोविड-19 के प्रति लापरवाह हुए लोग, नियमों के अनुपालन में होने लगी ढिलाई

नई दिल्ली । भले ही भारत में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा हो, लेकिन कोविड-19 की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बावजूद लोग मास्क पहनने से लेकर शारीरिक दूरी जैसे नियमों का उल्लंघन करने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया लोकल सर्कल के हालिया सर्वे में सिर्फ 30 फीसद लोगों ने माना कि उनके इलाके में मास्क पहनने के नियम का प्रभावी अनुपालन हो रहा है, जबकि सिर्फ 12 फीसद का कहना था कि उनके क्षेत्र में शारीरिक दूरी का पालन सही से हो रहा है।

पूछे गए फेस मास्क लगाने और शारीरिक दूरी संबंधी सवाल÷ एक तरफ जहां टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ रहा है, वहीं कोरोना वायरस में भी बदलाव हो रहे हैं। ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका में अलग-अलग वैरिएंट आ चुके हैं। ये पहले वाले से 50 फीसद से भी अधिक संक्रामक हैं। ऐसे में यह जानने का प्रयास किया गया कि मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के नियमों के अनुपालन के प्रति लोग कितने गंभीर हैं।

सर्वे में 238 जिलों के 8,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गईं। इनमें 51 फीसद लोग महानगरों या टियर एक वाले जिलों के रहने वाले थे। 28 फीसद टियर दो व 21 फीसद टियर तीन व चार के रहने वाले लोग सर्वे में शामिल रहे।

नहीं हो रहा शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन÷ लॉकडाउन खत्म होने के बाद व्यावसायिक व अन्य गतिविधियां शुरू हो गईं। वहीं, शारीरिक दूरी के नियम के अनुपालन में ढिलाई होने लगी। सर्वे में शामिल 56 फीसद लोगों का कहना था कि उनके इलाके में शारीरिक दूरी का अनुपालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ 12 फीसद ने कहा कि उनके इलाके में शारीरिक दूरी का खयाल रखा जा रहा है। 31 फीसद लोगों ने सीमित अनुपालन की बात कही। आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि टियर एक क्षेत्रों में शारीरिक दूरी का अनुपालन अपेक्षाकृत सही से हो रहा है। 15 फीसद लोगों ने कहा कि टियर दो वाले क्षेत्रों इस नियम का पालन सही से हो रहा है। टियर तीन व चार वाले क्षेत्रों में इसके अनुपालन की दर 10 फीसद रही।

कोविड-19 की महामारी में फेस मास्क कारगर रक्षा कवच साबित हो रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले मास्क वायरस को मुंह और नाक के जरिये व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। इससे बीमारी का खतरा कम हो जाता है। सितंबर 2020 में जब लोकल सर्कल ने सर्वे किया था तब 67 फीसद लोगों ने कहा था कि उनके इलाके में मास्क पहनने के नियम का अनुपालन सही से हो रहा है। यह दर इस साल 30 फीसद रह गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में लापरवाही ज्यादा÷ सर्वे में मास्क पहनने व शारीरिक दूरी जैसे नियमों के अनुपालन में जहां महानगरों तथा टियर एक, दो, तीन व चार श्रेणी के शहरों में लापरवाही की बात सामने आई, वहीं चौंकाने वाली बात यह रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन नियमों का अनुपालन न के बराबर हो रहा है। वहां सामाजिक गतिविधियां भी लगभग पहले की तरह संचालित होने लगी हैं।

वित्त विभाग ने स्वीकृत कर दिया है बजट

स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी मामलें में हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

जबलपुर (एजेंसी)।

मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट स्वीकृत की जाने की जानकारी हाईकोर्ट में पेश की गयी। चीफजस्टिस मोह. रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने बजट के संबंध में लिखित जानकारी पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

गौरतलब है कि मप्र राजय विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी 7 अप्रैल 2017 को मिलने के बाद प्रत्येक राज्य में स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी का गठन 9 माह में होना था, लेकिन मप्र में ऐसा नहीं हुआ जो अवैधानिक है। याचिका में जबलपुर स्थित डुमना में मिली एक विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया था। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार के ओर से बताया गया था कि स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी के गठन तथा उसके नियम के संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एक्ट के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड के गठन, प्रशिक्षित स्टॉफ के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता तथा संबंधित विभाग के कर्मचारियों को जागरूक करने अभियान चलाने आदि के मुददे उठाये गये थे। वहीं सरकार की ओर से पूर्व में कहा गया था कि इसके लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं है। बजट स्वीकृति के लिए सरकार ने दिसम्बर माह तक समय मांगा था। याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मौखिक रूप से युगलपीठ को बताया गया कि वित्त विभाग ने बजट स्वीकृत कर दिया है। जिसके बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। सुनवाई दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य अधिकारी व अधिवक्ता सत्यम अग्रवाल ने पैरवी की।

डोर टू डोर का टैक्स देने आगे आए व्यापारी

इंडियन कॉफी हाउस के 10 ब्रांचों के द्वारा जमा किया गया टैक्स

जबलपुर। नगर निगम द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020.21 के लिए राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजस्व विभाग का पूरा अमला मुस्तैदी के साथ मैदान में जुटकर करदाताओं से बकाया करों की राशि जमा कराने के कार्यो में लगे हुए हैं। राजस्व विभाग के उपायुक्त पी एन सनखेरे ने बताया कि 200 से अधिक व्यापारी निगम कार्यालय में स्वयं आकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सुविधा शुल्क जमा किये। उन्होंने बताया कि 200 लोगों से आज 3 लाख रुपए की वसूली हुई वहीं इंडियन कॉफी हाउस के 10 ब्रांचों गुलौआताल, करमचंद चौक, सुपर मार्केट, पुराना बस स्टैण्ड, कलेक्टर परिसर, ओमती पुलिस परिसर, कृषि विश्वविद्यालय परिसर, रॉझी, छटवीं बटालियन, मेडिकल कॉलेज एवं विजय नगर शाखा के प्रबंधकों द्वारा निगम में आकर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुल्क जमा कर शहर विकास में सहभागी बने।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन में जवाब के लिए मोहलत

जबलपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किये जाने को चुनौती देने वाले मामले में मंगलवार को सुनवाई बढ़ गई। चीफजस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष सरकार की ओर से जवाब के लिये समय की राहत चाही गई। जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिये मुलतवी कर दी।उल्लेखनीय है कि यह मामला एनयूएमएम के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया था। केन्द्र व रा%य सरकार की जांच एजेन्सियां भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने स्वतंत्र थी। केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2018 को एक्ट में संशोधन किया गया है। जिसके बाद जांच एजेन्सियों को भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही के लिए विभागीय अनुमत्ति लेना आवश्यक है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में कई लोक सेवकों के खिलाफजांच कई सालों से लंबित है। संशोधित एक्ट के कारण जांच एजेन्सी विभागीय अनुमति के बिना लोक सेवक के खिलाफकार्यवाही नहीं कर सकती है। विभागीय अनुमति नहीं मिलने के कारण लंबित शिकायात पर कार्यवाही नहीं हो सकेगी। इस बंधककारी नियम से जांच एजेन्सियों की कार्यवाही प्रभावित होगी। मामले की विगत 15 जनवरी को हुई प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये थे। याकिचाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की।

केंद्रीय रेलमंत्री गोयल ने किया यात्री सुविधाओं का लोकापर्ण

जबलपुर (एजेंसी)।

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार पीयूष गोयल द्वारा सोमवार को ग्वालियर स्टेशन पर तीन लिफ्टों का लोकार्पण, बैतूल और पाढुरना स्टेशनों पर दो-दो लिफ्टों का उद्घाटन, तीगॉव-चिचोंड़ा की तीसरी लाईन का समर्पण एवं रतलाम-चित्तौड़गढ़ नवविद्युतीकृत रेल खंड का लोकार्पण तथा रीवा से इतवारी के बीच ट्रेन का शुभारम्भ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया।कार्यक्रम में बताया गया कि रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड का विद्युतीकरण पूर्ण होने से डीजल की बचत होगी तथा हरित उर्जा को बढ़ावा मिलेगा। रतलाम-चित्तौड़गढ़ खंड डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलने से प्रति वर्ष लगभग की रू 27.54 करोड़ की बचत होगी।

जबलपुर से गोंदिया नए ट्रैक का मिलेगा लाभ

रेल मंत्रालय द्वारा रीवा से इतवारी के बीच एक नई यात्री गाड़ी का शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन रीवा से प्रारंभ होकर शाम 18.00 बजे सतना तथा 18.30 पर मैहर 19.30 पर कटनी होकर रात 21.10 बजे जबलपुर आएगी। जबलपुर से गोंदिया के मध्य नये ट्रैक से यह ट्रेन इतवारी के लिए रवाना होकर सुबह 6.50 बजे इतवारी-नागपुर स्टेशन पहुंचेगी। यह नई ट्रेन नंबर 01754 को 20 कोचों के द्वारा चलाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि जबलपुर से गोंदिया के बीच वर्षों पुरानी नैरो गेज लाइन को हाल ही में बड़ी रेल लाइन में तब्दील किया गया है जिसके कारण रीवा से नागपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर कम हो गई। इस दूरी के कम होने से यात्रा का समय में काफी बचत होगी।

ऑनलाइन जुड़े रहे रेल अधिकारी

आयोजन में महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में रेल विकास पर सारगर्भित संबोधन प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त महाप्रबंधक मध्य रेल, महाप्रबंधक पश्चिम रेल, महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेल भी प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्षयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह से जुड़े रहे। तत्पश्चात अपर महाप्रबंधक शोभन चौधुरी द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया तथा समारोह का संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती प्रियंका दीक्षित द्वारा किया गया।

कार्रवाई की सीएम चौहान ने ट्वीट कर जिला प्रशासन की तारीफ की

जबलपुर। राशन की कालाबाजारी करने वाले उचित मूल्य दुकान रिठौरी के विक्रेता के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सीएम चौहान ने ट्वीट कर जिला प्रशासन की तारीफ की है। श्री चौहान ने इस उचित मूल्य दुकान के विक्रेता की सम्पत्ति नीलाम कर राशि वसूल करने का निर्णय लेने के लिये भी जिला प्रशासन को बधाई दी है। ज्ञात हो की सोमवार 22 फरवरी को पनागर तहसील के रिठौरी स्थित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता ओम प्रकाश राय के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के आरोप में खमरिया पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान ग्राम रिठौरी के उचित मूल्य दुकान में कम पाये गये खाद्यान्न की कीमत विक्रेता की सम्पत्ति को नीलाम कर वसूलने के निर्देश भी दिये थे।

कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं

जबलपुर। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में आम लोगों की समस्यायें सुनी। कलेक्टर ने इस अवसर पर लोगों से आवेदन प्राप्त किये तथा अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिए।

अमृता राव

जैसी दिखती हैं उनकी छोटी बहन Preetika Rao, पहली बार में खा जाएंगे धोखा; Bigg Boss में भी आई थीं नजर

इश्क विश्क, मैं हूं ना, विवाह और वेलकम टू सज्जनपुर जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकीं अभिनेत्री अमृता रावके बारे में तो आप जानते ही हैं लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी बहन भी अभिनय में जलवा बिखेर रही हैं. दरअसल, यहां हम अमृता राव की बहन प्रीतिका राव के बारे में बात कर रहे हैं. टॉलीवुड और कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में प्रीतिका धीरे-धीरे अपनी पहचान बना रही हैं. हाल ही में प्रीतिका राव अपनी दूसरी कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलुरु में स्पॉट की गई थीं. अपनी अपकमिंग फिल्म में प्रीतिका राव कॉलीवुड अभिनेता बालाजी मनोहर (Balaji Manohar) और अच्युत कुमार के साथ नजर आएंगी. इसी बीच उन्होंने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी कि क्या वे वास्तव में अपनी सगी बहन अमृता जैसी दिखती हैं?

रिया और रीमा सेन से भी होती है प्रीतिका की तुलना

प्रीतिका राव ने कहा, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी बहन अमृता की तरह दिखती हूं, वास्तव में इस स्टेटमेंट को सुन मैं खुद आश्चर्य में हूं कि मेरा चेहरा अमृता से मिलता है. इस बात पर प्रीतिका जोर से हंसी और कहा कि मैं अमृता की तरह तो नहीं लेकिन मेरा चेहरा दूसरी एक्ट्रेसेज से जरूर मिलता है.

प्रीतिका राव ने बताया कि तमाम लोग मेरी तुलना रिया और रीमा सेन से करते हैं. अधिकतर लोगों को लगता है कि मैं रिया सेन के जैसी दिखती हूं.

बात अगर प्रीतिका की अपकमिंग कन्नड़ फिल्म की करें तो उसे श्रेयस सुधींद्र डायरेक्ट कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि सुधींद्र मेरे काफी पुराने दोस्त हैं लिहाजा उनके साथ काम करना काफी सहज है. जब उन्होंने फिल्म में मेरे किरदार को डिसकस करने के लिए बुलाया तो मैं उन्हें ना नहीं कह सकी. फिल्म में मुझे एक दिलचस्प किरदार मिला है और स्टोरी भी सच्ची कहानी पर आधारित है.

प्रीतिका ने Cadbury Dairy Milk में बिग बी संग किया है कामआपको बता दें कि प्रीतिका राव एक्टिंग से पहले फिल्मों की रिपोर्टिंग किया करती थीं. एक्टर और जर्नलिस्ट के अलावा प्रीतिका को सिंगिंग का भी काफी शौक है. उन्होंने फेमस सिंगर शान के साथ को गाया था जिसे लिसनर्स का जबरदस्त प्यार मिला था. आपको बता दें कि ये वही प्रीतिका हैं जिन्हें आपने के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के साथ देखा है.

प्रीतिका बिग बॉस सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट और झलक दिखलाजा सीजन 7 में गेस्ट बनकर आई थीं. इसके अलावा वे में भी नजर आई थीं.

राखी सावंत ने जताई मां बनने की इच्छा, बोलीं- विकी डोनर नहीं, बच्चे के लिए पिता चाहिए

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) बीते दिनों बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में धमाल मचाती नजर आई थीं. बिग बॉस 14 में राखी सावंत सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहीं. उन्होंने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और खूब तारीफें बटोरीं. यही नहीं शो के होस्ट सलमान खान ने भी राखी का सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. रविवार को हुए फिनाले में राखी सावंत 14 लाख रुपये की राशि लेकर शो से बाहर चली गईं. शो से निकलने के बाद राखी सावंत एक बार फिर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में हैं.

शो से निकलने के बाद एक बार फिर राखी सावंत ने परिवार और बच्चों को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की है. राखी सावंत का कहना है कि वह अब अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहती हैं. इसके साथ ही उन्होंने मां बनने की इच्छा भी जाहिर की है. राखी का कहना है कि वो मां बनना चाहती हैं और अपने बच्चे के लिए एक पिता चाहती हैं. राखी सावंत ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है.टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में राखी सावंत ने कहा, %मैं मां बनने पर फोकस करूंगी. मैं अपने बच्चे के लिए एक पिता चाहती हूं. विक्की डोनर नहीं. मैं अपने बच्चे को अपने पति रितेश के साथ मिलकर पालना चाहती हूं. मेरी प्राथमिकता मां बनना है. मैं सिंगल नहीं रहना चाहती. मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन मैं ऐसा करना चाहती हूं. मुझे उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा.

जैस्मीन भसीन संग शादी को लेकर अली गोनी बोले- मैं कुछ भी करूंगा

दोस्ती के बाद जब रिश्ता प्यार में बदल गया तो जैस्मीन भसीन और अली गोनी शादी को लेकर खुलकर बात करते नजर आए। हाल ही में अली गोनी 'बिग बॉस 14' से बाहर आने के बाद मीडिया संग रू-ब-रू हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जैस्मीन भसीन के पैरेंट्स को शादी के लिए मनाने के लिए वह कुछ भी करेंगे।

अली गोनी ने कहा कि जैस्मीन भसीन संग मैं पहले डेट पर जाना चाहूंगा। अब क्योंकि शो खत्म हो चुका है तो मैं अपने और जैस्मीन के बारे में तसल्ली से सोच सकता हूं। मैं उसके लिए बेस्ट चाहता हूं। मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं और मैं एक-एक करके चीजें करना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जैस्मीन भसीन के पैरेंट्स को शादी के लिए तैयार करने को लेकर कुछ भी करूंगा।

अली गोनी आगे कहते हैं कि मैं जैस्मीन को सपोर्ट करने के लिए शो में गया था। शो के दौरान ही मुझे अहसास हुआ कि जैस्मीन ही मेरे लिए वह लड़की है, जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं।

प्रोजेक्ट्स को लेकर जब अली गोनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें लेकर मैं जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट करूंगा। राहुल संग दोस्ती को लेकर अली ने कहा कि वह सच है और शो के बाद भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, हमेशा के लिए।

एडल्ट वीडियो केस में शर्लिन चोपड़ा होंगी गिरफ्तार ?

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का विवादों से पुराना नाता है. न्यूड फोटोशूट के जरिए चर्चा में छाईं शर्लिन चोपड़ा इन दिनों ऐसी ही एक वजह के चलते सुर्खियों में हैं. शर्लिन चोपड़ा 'एडल्ट कंटेंट'मामले में आरोपी हैं. शर्लिन चोपड़ा पर फ्री पॉर्न वेबसाइट्स पर अश्लील वीडियो पब्लिश करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. जिस पर शर्लिन चोपड़ा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी. अब इस मामले में आज बॉबे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

शर्लिन ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनका कंटेंट एक सदस्यता आधारित इंटरनेशनल पोर्टल के लिए था और उनका कंटेट चोरी कर लिया गया है. बता दें कि पिछले साल शर्लिन चोपड़ा पर फ्री पॉर्न वेबसाइट्स पर एडल्ट कंटेट पब्लिश करने का आरोप लगा था. इस मामले में शर्लिन पर आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और 67 के तहत धाराएं दर्ज हुई थीं.उस समय गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां पर उनकी जमानत याजिका खारिज कर दी गई थी. शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत को सेशन कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि एक आत्मनिर्भर महिला से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने चुनिंदा ग्रुप्स के अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए एडल्ट कंटेंट बनाए और उस कंटेंट को वेबसाइट पर पब्लिश करे. हांलाकि शर्लिन चोपड़ा ने इस मामले में अपनी सफाई देते हुए कहा था कि वो एक नहीं बल्कि दो कंपनीज की डायरेक्टर हैं. एफआईआर में बताई गई वेबसाइट में पायरेटेड कंटेंट है जो कॉपीराइट का उल्लंघन है. क्योंकि वे केवल ऑरिजनल प्लेटफॉर्म को ही कंटेंट देती हैं. शर्लिन का कहना था कि इस तरह से उनकी निजता का हनन तो हुआ ही है साथ ही ये उनका उत्पीड़न है जो वो बरसों से झेल रही हैं. जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइटों से वीडियो डाउनलोड करते हैं, वॉटरमार्क हटाते हैं और फ्री में अन्य साइट्स पर मुहैया करवाते हैं. आवेदन में कहा गया है कि शिकायतकर्ता यह नहीं समझ पाया है कि असली अपराधी कौन है.बता दें कि एक रिटायर्ड सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी मधुकर केनी ने 31 अक्टूबर, 2020 को एक पेन ड्राइव और कई एडल्ट कंटेट प्लेटफार्मों के खिलाफ साइबर पुलिस में शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि जब शर्लिन चोपड़ा का नाम सर्च इंजन में डाला तो उनके अश्लील वीडियो स्क्रीन पर आ गए.

संक्षिप्त समाचार

लाइट्स को लेकर चिंतित, खिलाड़ियों को तेजी से ढलना होगा: कोहली

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने चिंता जताई कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लाइट्स से दृश्यता पर असर पड़ सकता है और खिलाड़ियों को जल्दी ही खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। दुनिया के इस सबसे बड़े नव सज्जित क्रिकेट स्टेडियम में पारंपरिक फ्लडलाइट नहीं है बल्कि छत के परिमाप में ही एलईडी लाइट्स फिट की गई है। यह दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के 'रिंग आफ फायर' की तरह है जिससे फील्डिंग करने वाली टीम को दिक्कत आ सकती है। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले टॉस के समय कहा, ''यहां माहौल काफी रोमांचक है। मैं सीटों के रंग से ज्यादा लाइट्स को लेकर चिंतित हूं।'' उन्होंने कहा, ''ऐसी लाइट्स में गेंद को देखना मुश्किल होता है। इसी तरह के स्टेडियम में हमने दुबई में भी खेला है। इसके अनुरूप जल्दी ढलना होगा।'' दुबई में पिछले साल आईपीएल के दौरान इस तरह की लाइट में कई आसान कैच भी फील्डरों से छूटे थे।

इंग्लैंड का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफदिन रात के तीसरे क्रिकेट टेस्ट में बुधवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को और कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया। इंग्लैंड टीम में जोफ्रा आर्चर, जाक क्रॉली, जेम्स एंडरसन और जॉनी बेयरस्टॉ की वापसी हुई है। वहीं मोईन अली, रोरी बर्न्स, डेन लॉरेंस और ओली स्टोन को बाहर किया गया है। चार मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1.1 से बराबर है।

भारत बनाम बांग्लादेश सड़क सुरक्षा विश्व सीरिज पांच मार्च से

मुंबई, (वेबवार्ता)। इंडिया लीजैंड्स का सामना सड़क सुरक्षा विश्व क्रिकेट सीरिज के पहले मैच में पांच मार्च को रायपुर में बांग्लादेश लीजैंड्स से होगा। ये मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेले जायेंगे। इंग्लैंड लीजैंड्स का सामना सात मार्च को बांग्लादेश लीजैंड्स से होगा। पहला सेमीफाइनल 17 मार्च को और दूसरा 19 मार्च को होगा। फाइनल 21 मार्च को खेला जायेगा। करीब 65000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम में 50 प्रतिशत दर्शकों को प्रवेश दिया जायेगा। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, मुथैया मुरलीधरन और छह क्रिकेट देशों (भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश) के खिलाड़ी इससे जुड़े हैं। इसका आयोजन सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिये किया गया है। पहला सत्र 11 मार्च 2020 से होना था जो कोरोना महामारी के कारण रद्द करना पड़ा।

कोको गॉ एडीलेड अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में

एडीलेड, (वेबवार्ता)। अमेरिका की 16 वर्षीय खिलाड़ी कोको गॉ ने बुधवार को यहां एडीलेड अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पेत्रा मार्टिच पर जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। गॉ ने छठी वरीयता प्राप्त मार्टिच को 5-7, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। वह हाल में समाप्त हुए आस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में पांचवीं वरीय एलिना स्वितोलिना से हार गयी थी। अब क्वार्टरफाइनल में उनका सामना अमेरिका की शेल्बी रोजर्स से होगा। अन्य मैचों में दूसरी वरीय बेलिंडा बेनसिच ने मिसाकी डोई पर 6-1 6-3 से जीत दर्ज की। स्टोर्म सैंडर्स ने सातवीं वरीय युलिया पुतिनतसेवा को हराकर उलटफेर किया। जिल टेचमैन और अनास्तासिया सेवास्तोवा ने भी अपने मुकाबले जीत लिये।

भारतीय गोल्फर जीव, लाहिड़ी ने वुड्स के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। भारत के शीर्ष गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और अनिर्बान लाहिड़ी समेत दुनिया भर के खेल समुदाय और खेलप्रेमियों ने महान गोल्फखिलाड़ी टाइगर वुड्स के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। वुड्स लॉस एंजिलिस में एक कार दुर्घटना में घायल हो गए और उनके पैरों का आपरेशन करना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा से लेकर महान मुक्केबाज माइक टायसन और विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों ने इस हादसे पर दुख जताया। जीव मिल्खा सिंह ने ट्वीट किया, ''हम टाइगर वुड्स के लिये प्रार्थना कर रहे हैं। हमने आपको अतीत में भी अनहोनी को होनी करते देखा है। इससे भी जल्दी उबर जाइये।'' लाहिड़ी ने लिखा, ''आपने जिन चुनौतियों का सामना किया है, उनकी कल्पना करना भी कठिन है। आप जल्दी स्वस्थ हो जाइये। गोल्फजगत हाथ जोड़कर आपके लिये प्रार्थना कर रहा है।'' वुड्स उस समय एक टीवी शूट के लिये जा रहे थे और कार में अकेले थे जब सड़क के बीच 'डिवाइडर' से उनकी कार टकरा गई और दो लेन पार करते हुए कई बार पलट गई। डॉक्टरों को उनके दाहिने पैर में लगी गंभीर चोटों के लिये रॉड्स, स्क्रू और पिनें डालनी पड़ी हैं।

गूलिया ने स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में विश्व चौम्पियन को हराया

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। ज्योति गूलिया (51 किलो) ने बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में दो बार की विश्व चौम्पियन कजाखस्तान की नाजिम काइजेबी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि भारत के तीन मुक्केबाज दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गए। विश्व युवा चौम्पियन 2017 गूलिया ने 2014 और 2016 की सीनियर विश्व चौम्पियनशिप विजेता काइजेबी को 3.2 से मात दी। हरियाणा की यह मुक्केबाज 2019 की राष्ट्रीय चौम्पियन भी है। अब उसका सामना रोमानिया की पेरिजोक लाकरामियोआरा से होगा। भारत की भाग्यवती कचारी ने रूस की अन्ना गालिमोवा को 5.0 से हराकर 75 किलोवर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पुरूष वर्ग में नवीन बूरा ने आर्मेनिया के आर्मेन एम को हराकर 69 किलोवर्ग के अंतिम आठ में प्रवेश किया। वहीं नवीन कुमार (91 किलो) फ्रांस के विलफ्राइड फ्लोरेंटिन से 5.0 से हार गए जबकि अंकित खताना (75 किलो) को बेलारूस के विक्टर डी ने 3.2 से हराया। लाइट हैवीवेट (81 किलो) में सचिन कुमार को आर्मेनिया के गोर एन ने 5.0 से मात दी। टूर्नामेंट में 30 देशों के मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। भारत ने अपनी 12 सदस्यीय टीम भेजी है।

भारत के पहले म्यूजिक लीग चौंपियनशिप में शामिल होंगे रैना

नयी दिल्ली, (वेबवार्ता)। भारत के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना भारत के पहले म्यूजिक लीग चौंपियनशिप 'इंडियन प्रो म्यूजिक लीग (आईपीएमएल) में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आईपीएमएल 'जी टीवी' की एक पहल है। यह संगीत प्रतियोगिता है जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से छह टीमें होंगी। 34 वर्षीय रैना इस शो में अपने राज्य की टीम 'यूपी दबंग्स' के ब्रांड एंबेसडर होंगे। रैना ने कहा, ÷संगीत या गायन समय बिताने का पसंदीदा माध्यम और शौक है। खेलने के दौरान भी इससे मुझे मदद मिली है। इसलिए मैं क्रिकेट के बाद की मेरी पसंदीदा चीजों को समय दे रहा हूं। ÷ पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इससे पहले भी अपने गायन की प्रतिभा दिखा चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इस शो के ब्रांड एंबेसडर होंगे। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, गोविंदा, राजकुमार राव, रितेश देशमुख, जेनेलिया और बॉबी देओल भी अलग-अलग टीमों के ब्रांड एंबेसडर होंगे।

लगातार दूसरे साल अंडर 19 यूरोपीय चौम्पियनशिप रद्द

नियोन, (वेबवार्ता)। सालाना अंडर 19 महिला और पुरूष फुटबॉल यूरोपीय चौम्पियनशिप लगातार दूसरे साल रद्द कर दी गई। युएफा ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सरकार के नियमों के मद्देनजर यह फैसला लेना पड़ा। युएफा ने कहा,'' इस टूर्नामेंट के लिये टीमों की यात्रा और उनके रहने का बंदोबस्त कर पाना कठिन था।'' इसमें पुरूष टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा देशों को भाग लेना था जबकि आठ टीमों का फाइनल 30 जून से रोमानिया में होना था। महिला क्वालीफायर अप्रैल में खेले जाने थे जबकि फाइनल बेलारूस में जुलाई में होना था।

आल इंग्लैंड ड्रॉ: सिंधु की राह आसान, साइना को कठिन ड्रॉ

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। मौजूदा विश्व चौम्पियन पी वी सिंधु को प्रतिष्ठित आल इंग्लैंड बैडमिंटन चौम्पियनशिप में आसान ड्रॉ मिला है जबकि साइना नेहवाल को कठिन प्रतिद्वंद्वियों से भिड़ना पड़ेगा। टूर्नामेंट 17 से 21 मार्च के बीच बर्मिंघम में खेला जायेगा। स्विस ओपन के बाद आल इंग्लैंड ओपन 2021 इस साल का दूसरा टूर्नामेंट होगा जिसमें तोक्यो ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिये रैंकिंग अंग मिलेंगे। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा मंगलवार को जारी ड्रॉ के अनुसार ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु पहले दौर में मलेशिया की सोनिया चिया से खेलेगी। शुरूआती दौर के मुकाबले जीतने पर क्वार्टर फाइनल में उसका सामना जापान की अकाने यामागुची और सेमीफाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन से हो सकता है। मारिन को टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता मिली है जबकि सिंधु को पांचवीं वरीयता दी गई है। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना को पहले दौर में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट से खेलना है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पारूपल्ली कश्यप को पहले ही मैच में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोता का सामना करना है। किदाम्बी श्रीकांत पहले दौर में इंडोनेशिया के टॉमी सुगिआर्तो से खेलेंगे जबकि विश्व चौम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता बी साइ प्रणीत फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव का सामना करेंगे। भारतीय खिलाड़ी तीन मार्च से शुरू हो रहे स्विस ओपन में भी भाग लेंगे। साइना और श्रीकांत को तोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने के लिये और समय मिलेगा क्योंकि बीडब्ल्यूएफ ने क्वालीफिकेशन की अवधि बढा दी है।

आल इंग्लैंड ओपन के ड्रॉ:

महिला एकल:
पी वी सिंधु बनाम सोनिया चिया (मलेशिया)
साइना नेहवाल बनाम मिया ब्लिचफेल्ट (डेनमार्क)

पुरूष एकल:
किदाम्बी श्रीकांत बनाम टॉमी सुगिआर्तो (इंडोनेशिया)
पारूपल्ली कश्यप बनाम केंतो मोमोता (जापान)
लक्ष्य सेन बनाम के वांगचारोन (थाईलैंड)
एच एस प्रणय बनाम लियू डारेन (मलेशिया)
समीर वर्मा बनाम वाय कोल्हो (ब्राजील)
बी साइ प्रणीत बनाम टोमा जूनियर पोपोव (फ्रांस)

पुरूष युगल:
सात्विक साइराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी बनाम इलोइ एडम और जूलियन मायो (फ्रांस)
एम आर अर्जुन और ध्रुव कपिला बनाम ओंग यू सिन और टियो ई यि (मलेशिया)

महिला युगल:
अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी बनाम बी एमसार्ड और एन एमसार्ड (थाईलैंड)
मेघना जे और पूर्विषा राम बनाम अलेक्जेंद्रे बोए और मेटे पाउलसेन (डेनमार्क)
अश्विनी भट और शिखा गौतम बनाम सी बिर्च और लौरेन स्मिथ (इंग्लैंड)

मिश्रित युगल:
ध्रुव कपिला और मेघना जे बनाम प्रवीण जोर्डन और मेलाती ओ (इंडोनेशिया)
सात्विक साइराज रांकिरेड्डी और अश्विनी पोनप्पा बनाम युकी कानेको और मिसाकी मत्सुतोमो (जापान)
प्रणव जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी बनाम मैक्स फ्लिन और जेसिका पुग (इंग्लैंड)

मुक्केबाजी: ज्योति ने 2 बार की विश्व चौंपियन को हराया, 3 भारतीय क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली, (वेबवार्ता)। भारत की उभरती हुई महिला मुक्केबाज ज्योति गुलिया ने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए दो बार की विश्व चौंपियन कजाखस्तान की नाजिम किजाएबे को हराकर बुल्गारिया के सोफिया में जारी 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट के दूसरे दिन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया।
महिला वर्ग में 2017 की विश्व यूथ चौंपियन तथा 2019 की राष्ट्रीय चौंपियन गुलिया (51 किग्रा) ने कजाखस्तान की नाजिम किजाएबे को 3-2 से मात दी। भाग्यबती कचारी ने महिलाओं की 75 किग्रा में रूस की एना गेलिमोवा को 5-0 से शिकस्त दी।
पुरुषों के वर्ग में नवीन बूरा ने 69 किग्रा में अर्मेनिया के एर्मन मशाकेरीयान को 3-2 से हराकर अंतिम-8 में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में अब बूरा का सामना ब्राजील के इरावियो एडसन से होगा। बूरा के अलावा मंजीत सिंह (91 किग्रा) भी तीसरे दिन रिंग में उतरेंगे। हालांकि चार अन्य पुरुषों को प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा। एशियाई चौम्पियनशिप के रजत पदक विजेता कविंदर सिंह बिष्ट (57 किग्रा) यूक्रेन के मायकोला बट्सेंको से 3-2 से हार गए, जबकि अंकित खटाना (75 किग्रा) को बेलारूस के विकट डियाजस्केविच से हार का सामना करना पड़ा।
सचिन कुमार (81 किग्रा) और नवीन कुमार (91 किग्रा) को क्रमशः आर्मेनिया ए के गोर नेरेशियन और फ्रांस के विल्फ्रेड फ्लोरेंटिन के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा।

तेंदुलकर ने इशांत के 100वें टेस्ट से पहले उनकी प्रशंसा की

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को इशांत शर्मा की उनके 100वें टेस्ट से पहले प्रशंसा की और कहा कि खेल के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रारूप में इतने सारे मैच खेलना किसी भी क्रिकेटर और सबसे ज्यादा एक तेज गेंदबाज के लिये शानदार उपलब्धि है। इशांत (32 वर्ष) कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच में खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ''100 टेस्ट मैच खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिये शानदार उपलब्धि है, विशेषकर एक तेज गेंदबाज के लिये। अंडर-19 के दिनों से आपको खेलते देखा है और आपके पहले टेस्ट में आपके साथ खेला था। टीम इंडिया के लिये आपकी सेवाओं के लिये आप पर गर्व है।'' मास्टर बल्लेबाज ने लिखा, ''सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से सेवा जारी रखिये। आपको इस उपलब्धि के लिये बधाई।'' चेन्नई में इस महीने के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान इशांत टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट चटकाने वाले छठे भारतीय और देश के तीसरे तेज गेंदबाज बन गये थे जिसमें वह महान पूर्व कप्तान कपिल देव और अनिल कुंबले के साथ शामिल हो गये। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने स्टार स्पोर्ट्स शो 'क्रिकेट कनेक्टिड' में इशांत के बारे में बात करते हुए कहा, ''किसी भारतीय तेज गेंदबाज के लिये ही नहीं बल्कि किसी भी तेज गेंदबाज का 100 टेस्ट मैच खेलना बड़ी उपलब्धि है। जब लोग इशांत शर्मा की लेंथ के बारे में बात करते थे तो उन्होंने अपनी लेंथ में बदलाव किया जो टेस्ट क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण है।'' इशांत ने 11 बार पांच विकेट चटकाये हैं और एक मैच में एक बार 10 विकेट झटके थे। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को फेंके गये उनके स्पैल के बारे में अब भी भारतीय क्रिकेट जगत चर्चा की जाती है। नेहरा ने कहा, ''पिछले 18 से 24 महीनों में उनकी गेंद स्टंप के करीब भी बायें हाथ के बल्लेबाजों के लिये बहुत अच्छी तरह जा रही है और 'ओवर द स्टंप' तो भूल ही जाइये।'' उन्होंने कहा, ''यह दिखाता है कि वह अपने खेल के बारे में सोच रहा है, नई चीजें डालने की कोशिश कर रहा है और नतीजे भी उसके पक्ष में ही रहे हैं। यह भारत के लिये बहुत शानदार चीज है।''

मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल

लॉस एंजिलिस, (वेबवार्ता)। मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स यहां एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए जब उनकी कार सड़क के बीच में बने विभाजक से टकराकर कई बार घूम गई। वुड्स को विंडशील्ड से बाहर निकाला गया और उनके पैरों का आपरेशन चल रहा है। वह उस समय कार में अकेले थे जब सड़क के बीच 'डिवाइडर' से उनकी कार टकरा गई और दो लेन पार करते हुए कई बार घूम गई। अधिकारियों ने मीडिया को यह जानकारी दी। हादसे में कोई और कार शामिल नहीं थी। वुड्स चौकन्ने थे और उन्होंने अपनी ऊंगलियों का इस्तेमाल करके आगे की विंडशील्ड खोली जिससे उन्हें बाहर निकाला जा सका। लॉस एंजिलिस काउंटी के शेरीफ एलेक्स विलानुएवा ने कहा,'' उनका एयरबैग खुल गया था और कार के भीतर के हिस्से में उन्हें कुशन मिल गया जिससे वह इस हादसे में बच सके।'' उनके दोनों पैरों में काफी चोट आई है। दमकल अधिकारियों ने कहा कि अभी यह पता नहीं चल सका है कि क्या वह अपने पैर गंवा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि उनके शरीर से अल्कोहल या किसी अन्य पदार्थ की गंध नहीं आ रही थी। यह भी पता नहीं चल सका है कि कार की रफ्तार क्या थी। शेरीफ के सहायक कार्लोस गोंजालेस ने बताया कि इस घुमावदार सड़क पर हादसे आम बात है। उन्होंने कहा,'' वुड्स किस्मतवाले हैं कि जिंदा बच गए है।'' वुड्स सप्ताह के आखिर में जेनेसिस इंविटेशनल टूर्नामेंट के लिये लॉस एंजिलिस में थे। उन्हें सोमवार और मंगलवार को डिस्कवरी के गोल्फ टीवी के लिये शूटिंग करनी थी। उन्होंने सोमवार को एक फोटो भी ट्वीट की थी। पंद्रह बार के मेजर चौम्पियनशिप विजेता वुड्स की दिसंबर में कमर की सर्जरी हुई थी जो उनकी पांचवीं सर्जरी थी। उन्होंने 2019 में ही गोल्फ कोर्स पर वापसी करके पांचवां मास्टर्स खिताब जीता था। उन्होंने आखिरी बार 20 दिसंबर को फ्लोरिडा में पीएनसी चौम्पियनशिप खेली थी जिसमें वह अपने बेटे के साथ उतरे थे। वुड्स तीसरी बार कार से जुड़े हादसे के शिकार हुए हैं।इससे पहले 2009 में तड़के 'थैंक्सगिविंग' के बाद लौटते समय उनकी कार पेड़ से टकरा गई थी।

100वां टेस्ट पूरा करने पर राष्ट्रपति ने ईशांत को भेंट की स्पेशल कैप और स्मृति चिन्ह

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा कपिल देव के बाद 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 100वां टेस्ट मैच पूरा करने ईशांत को स्पेशल कैप और स्मृति चिन्ह भेंट किया। ईशांत ने बुधवार से इंग्लैंड के साथ मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही यह उपलब्धि हासिल की। यह मैच डे-नाइट हो रहा है।
इस स्टेडियम की क्षमता 1 लाख 10 हजार है और यह अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। इसी स्टेडियम में भारत के सर्वकालिक महान टेस्ट गेंदबाज अनिल कुम्बले ने भी अपना 100वां टेस्ट खेला था।
साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में अपने टेस्ट करियर का आगाज करने वाले ईशांत ने अब तक कुल 99 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 32.22 की औसत से 302 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने घर में 39 टेस्ट मैचों में 103 विकेट जबकि घर से बाहर 60 टेस्ट मैचों में 199 विकेट झटके हैं। घर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 78 रन पर नौ विकेट और घर से बाहर 108 रन पर 10 विकेट हैं।
ईशांत ने 100 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने के बाद मैच शुरू होने से पहले टॉस के बाद कहा, मेरे लिए अभी तक का करियर का अनुभव काफी अच्छा रहा है। मैंने यहां तक पहुंचने के दौरान इसका काफी लुत्फउठाया और टीम के साथ इसका पूरा आनंद लिया है।
ईशांत का भारतीय टीम के साथ यह दूसरा पिंक बॉल टेस्ट है। पहले पिंक बॉल टेस्ट में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफपांच विकेट लिए थे।
उन्होंने कहा, जब हमने बांग्लादेश के खिलाफअपना पहला पिंक बॉल टेस्ट खेला था, तो उस समय लाल गेंद की तरह ही पिंक बॉल भी स्विंग हो रही थी। हालांकि यह बताना मुश्किल है कि गेंद कितनी स्विंग होगी।

निशानेबाजी विश्व कप के लिये पृथकवास अवधि छोटी ओर सुविधाजनक होगी: रीजीजू

अहमदाबाद, (वेबवार्ता)। अगले महीने होने वाले निशानेबाजी विश्व कप में भाग लेने के लिये निशानेबाजों को प्रेरित करने के लिये खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को वादा किया कि टूर्नामेंट में पृथकवास की अवधि छोटी और सुविधाजनक होगी। आईएसएसएफ संयुक्त विश्व कप दिल्ली में 18 से 29 मार्च के बीच होगा जिसमें ब्रिटेन और ब्राजील समेत 40 देशों के निशानेबाज भाग ले रहे हैं। रीजीजू ने मोटेरा स्टेडियम के दौरे के बाद कहा,'' मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि भारत में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन ऐसे होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ खिलाड़ियों को लंबे समय तक पृथकवास में नहीं रहना होगा। '' हाल ही में मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि 14 दिन के कड़े पृथकवास से निशानेबाजों को रियायत दी जाये और विदेश से आने वाले दल को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाये। रीजीजू ने कहा कि टीकाकरण स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता हे लेकिन वे यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतियोगियों को असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा,'' हमारे खिलाड़ी भी 14 . 15 दिन पृथकवास में रह गए तो उन्हें असुविधा होगी। इसलिये हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि बाहर से आने वाले दल का रवानगी से पहले और पहुंचने पर कोरोना टेस्ट हो। हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि उन्हें असुविधा नहीं हो।'' तोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को टीका देने की प्रक्रिया के बारे में रीजीजू ने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता कोरोना योद्धा हैं। उन्होंने कहा,'' इसके बारे में फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा और पहले ही तय हो चुका है कि प्राथमिकता कोरोना योद्धा होंगे। सबसे पहले डाक्टर, नर्स, सुरक्षाकर्मियों को टीके दिये जा रहे हैं।इसके बाद खिलाड़ियों और बाकियों का नंबर आयेगा।'' उन्होंने कहा,'' तोक्यो जाने वाले खिलाड़ी, तकनीकी टीमें, ट्रेनर को भी प्राथमिकता मिलेगी लेकिन समग्र प्राथमिकता सूची के बारे में फैसला गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। खेल मंत्रालय की प्राथमिकता खिलाड़ी हैं।'' फिलहाल खेल महासंघ राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के तहत आते हैं लेकिन खेलमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय की जरूरतों के अनुसार इसमें बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा,'' हम एक नया कोड बनाना चाहते हैं जिसमें आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखा जायेगा। हम ऐसे प्रावधान बदलना चाहते हैं जिसमें अलग तरह के खेलों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जैसे गोल्फ, घुड़सवारी, आइस हॉकी, स्कीइंग ऐसे खेल हैं जो हर राज्य में नहीं खेले जाते।'' रीजीजू ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता के डी जाधव के नाम पर एक खेल केंद्र का नामकरण किया जायेगा। उन्होंने यह बात ऐसे समय पर कही जब 1952 हेलसिंकी ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता जाधव को पद्मश्री देने की मांग हो रही है।

टाटा मुम्बई मैराथन का आयोजन 30 मई को

मुम्बई, (वेबवार्ता)। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित मैराथन के प्रोमोटर्स प्रोकैम इंटरनेशनल ने घोषणा की है कि टाटा मुंबई मैराथन (टीएमएम) का आयोजन इस वर्ष 30 मई को होगा। यह निर्णय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक निकायों सहित राज्य और नागरिक प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श और सहयोगात्मक प्रयासों के बाद लिया गया है। प्रौकैम इंटरनेशनल प्रचलित सरकारी प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित माहौल में पूर्ण-मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर के रन में सीमित भागीदारी के साथ ऑन-ग्राउंड इवेंट का संचालन करेगा। सीमित संख्या में लोग अपने निर्धारित स्थान से रेस में हिस्सा ले सकेंगे जबकि भारत और दुनिया भर के प्रतिभागी, आधिकारिक टीएमएम 2021 एप्प के माध्यम से टीएमएम में अपनी पसंद के स्थान से हिस्सा ले सकेंगे।
प्रमोटर्स सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों, वॉलंटियर्स और रनिंग बिरादरी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के के लिए स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे। यह पुनर्निर्धारित तारीख धावकों को तैयारी करने का आवश्यक समय देगा और इसके माध्यम से वे टाटा मुम्बई मैराथन के 18वें संस्करण में पूरी तैयारी के साथ हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा, गैर-सरकारी संगठनों, कंपनियों और व्यक्तिगत फंडरों को प्रभावी आउटरीच के लिए मूल्यवान समय मिलेगा, जिससे कि वे अपने चुने हुए प्रयोजन के लिए धन जुटा सकेंगे।